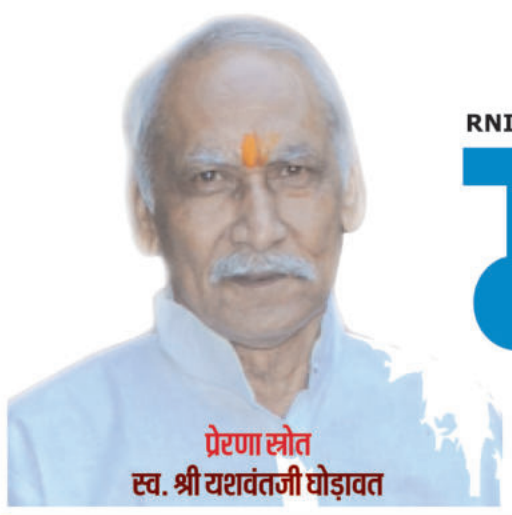

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

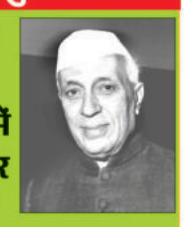

अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं।

जवाहरलाल नेहरू

वर्ष-08, अंक - 46 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 03 सितम्बर 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

नेपाल की त्रासदी... पत्रकारिता की असल परीक्षा

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

नेपाल में बाढ़ और मलबे ने तबाही का ऐसा दृश्य खड़ा किया है, जहां हर मलबे के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं, किसी परिवार की उम्मीद् दबी हो सकती है। रासुवा और नुवाकोट समेत प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे या लापता मजदूरों की तलाश हो रही है। दूसरी ओर कई परिवार अब भी इस उम्मीद् में हैं कि, शायद अगली खबर उनके किसी अपने के सुरक्षित होने की हो।

आपदा के ऐसे समय में पत्रकारिता का काम केवल यह बताना नहीं है कि, कितने लोग मारे गए और कितने लापता हैं। आंकड़े जरूरी हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी मानवीय पीड़ा को समझना उससे भी जरूरी है। हर बड़ी आपदा कुछ सवाल छोड़ जाती है, क्या समय रहते चेतावनी दी गई थी...? प्रशासन कितना तैयार था...? राहत और बचाव कितनी तेजी से पहुंचा...? और भविष्य में ऐसी तबाही को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है...? यहीं से समाचार और पत्रकारिता के बीच का फर्क सामने आता है।

नेपाल की मौजूदा त्रासदी की भारतीय मीडिया में हो रही कवरेज का एक बड़ा हिस्सा राहत, बचाव और मानवीय पहलुओं को सामने ला रहा है। प्रभावित लोगों की परेशानी और बचाव दल की मेहनत दिखाना जरूरी है। इससे दूर बैठे लोगों को संकट की वास्तविकता समझने में मदद मिलती है। लेकिन आपदा की कवरेज में एक महीन रेखा होती हैं। खबर दिखाने और त्रासदी को तमाशा बना देने के बीच की रेखा।

मलबे में दबा घर, सुरंग में चल रहा बचाव अभियान

बाढ़ के बीच फंसा परिवार या किसी व्यक्ति की आंखों में अपने प्रियजन को खोजती बैचेनी के ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन पत्रकारिता की जिम्मेदारी केवल ऐसे दृश्य दिखाकर खत्म नहीं हो जाती। असली सवाल यह है कि, बचाव अभियान कहां तक पहुंचा...? कितने लोग सुरक्षित हैं...? बाधाएं क्या हैं...? प्रशासन ने क्या किया...? चेतावनी व्यवस्था कहां तक काम आई...? और जो कमियां सामने आई हैं, उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है...?

आपदा की तस्वीर जरूरी है, लेकिन तस्वीर के पीछे का सवाल उससे ज्यादा जरूरी

2015 के नेपाल भूकंप के बाद

भारतीय मीडिया के एक हिस्से की कवरेज को लेकर नेपाल में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। सामाजिक माध्यमों पर 'भारतीय मीडिया वापस जाओ' जैसे नारे भी सामने आए थे। उस प्रसंग को केवल पुराने विवाद के रूप में याद करना पर्याप्त नहीं है। उसे पत्रकारिता के लिए एक सबक की तरह देखना चाहिए।

ग्यारह साल बाद फिर वही कसौटी सामने है। क्या हम पड़ोसी देश की त्रासदी को वहां के लोगों की संवेदनाओं और गरिमा के साथ दिखा रहे हैं...?

आपदा के दौरान आंकड़ों की विश्वसनीयता भी बड़ी जिम्मेदारी है। शुरुआती दौर में मृतकों और लापता लोगों की संख्या बदलती रहती है। ऐसे में अपुष्ट आंकड़ों को निश्चित तथ्य की तरह पेश करना गलत सूचना फैला सकता है। उससे भी बड़ी बात यह कि, किसी परिवार के लिए 'लापता' सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता। वह एक चेहरा, एक रिश्ता और एक पूरी जिंदगी होती है। इसलिए किसी पीड़ित के आंसुओं को कैमरे में कैद करने से पहले यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि, क्या उस समय उसे कैमरे की जरूरत है या सहारे की...? पत्रकार को घटना दिखानी है, लेकिन पीड़ित की गरिमा की कीमत पर नहीं।

भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ सीमाओं और कूटनीति तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच गहरे सामाजिक और मानवीय संबंध हैं। संकट की इस घड़ी में भारत की ओर से मिलने वाली सहायता और सहयोग महत्वपूर्ण हैं, उसकी खबर भी होनी चाहिए। लेकिन इस कवरेज का केंद्र, मदद पाने वाले लोगों की जरूरतें हों, न कि केवल मदद करने वाले देश की उपलब्धि।

मानवीय संकट को राष्ट्रीय श्रेष्ठता की कहानी में बदल देना न नेपाल के हित में है, न भारत के और न पत्रकारिता के, इसलिए भारतीय मीडिया की पूरी कवरेज को एक ही रंग में देखना उचित नहीं होगा। जहां अच्छी और जिम्मेदार रिपोर्टिंग हो रही है, उसकी सराहना होनी चाहिए। जहां सनसनी, अतिनाटकीय प्रस्तुति या अपुष्ट जानकारी का सहारा लिया जा रहा है, वहां सवाल भी उठने चाहिए।

आखिर पत्रकारिता की विश्वसनीयता इसी संतुलन से बनती है। तेज होने के साथ सही, प्रभावशाली होने के साथ संवेदनशील और सवाल पूछने के साथ जिम्मेदार।

2015 का 'भारतीय मीडिया वापस जाओ' प्रसंग भारतीय पत्रकारिता के लिए एक असहज स्मृति जरूर है, लेकिन उससे सीखने का अवसर आज भी मौजूद है। नेपाल की मौजूदा त्रासदी हमें याद दिला रही है आपदा के बीच पत्रकार का कैमरा सिर्फ मलबे की तस्वीर नहीं लेता, वह समाज के सामने एक आईना भी रखता है।

उस आईने में केवल तबाही दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। उसमें प्रशासन की तैयारी, व्यवस्था की कमियां, बचावकर्मियों की मेहनत, पीड़ितों का दर्द और भविष्य के लिए जरूरी सबक भी दिखाई देने चाहिए।

क्योंकि आपदा के समय पत्रकारिता की असली सफलता यह नहीं कि, उसने कितने भयावह दृश्य दिखाए। असली सफलता यह है कि, उसने कितनी सच्ची सूचना दी, कितने जरूरी सवाल पूछे और जिन लोगों पर त्रासदी गुजरी, उनकी आवाज को कितनी गरिमा के साथ दुनिया तक पहुंचाया। नेपाल की त्रासदी इसलिए सिर्फ राहत और बचाव की परीक्षा नहीं है। यह पत्रकारिता की संवेदना, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी की भी परीक्षा है।

बाढ़ से 1100 से अधिक मौतें, हजारों लापता, नए खतरे की भी चेतावनी

काठमांडू,एजेंसी।

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से तबाही का सिलसिला जारी है। बुधवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई। सुरक्षाबलों ने आठ जिलों से और शव बरामद किए हैं। लगातार रुक-रुककर हो रही बारिश और कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाइयां आ रही हैं। इस बीच देश के कई हिस्सों में बाढ़ की नई चेतावनी जारी होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करीब 4 हजार लोग अब भी लापता हैं। इनमें 583 विदेशी नागरिक और 83 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। राहत एवं बचाव अभियानों के दौरान अब तक करीब 12 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।

यह भीषण आपदा 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने अथवा हिमस्खलन के बाद आई अचानक बाढ़ के कारण हुई। इससे उत्तरी और मध्य नेपालके कई कस्बों तथा गांवों में भारी नुकसान हुआ है। हिमालयी क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी में अचानक आए तेज बहाव ने निचले इलाकों में तबाही मचा दी। बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए। कई महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। आपदा का असर सीमा पार चीन तक भी पहुंचा है। वहां 16 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है, जबकि तिब्बत क्षेत्र में करीब 550 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

नेपाल में चितवन जिले से सबसे अधिक 321 शव बरामद किए गए हैं। इसके बाद नवलपरासी पूर्व से 216, नवलपरासी पश्चिम से 170, नुवाकोट से 142, गोरखा से 65, धाडिंग से 57, रसुवा से 41 और तनहुन से 38 शव बरामद हुए हैं।

चिकित्सा केंद्रों पर अपने लापता परिजनों की तलाश में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लोग अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें लेकर अस्पतालों और संबंधित केंद्रों पर लगाए गए मृतकों के चित्रों में पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। देशभर के 21 अस्पतालों में अज्ञात शव रखे गए हैं। कई शव लंबे समय तक पानी में रहने के कारण खराब हो चुके हैं, जबकि कुछ शव केवल आंशिक अवशेषों के रूप में बरामद हुए हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

अधिकारियों के अनुसार अब तक बरामद शवों में पहचान होने के बाद केवल 60 शव परिजनों को सौंपे जा सके हैं। वहीं करीब 700 शवों को आवश्यक दस्तावेजीकरण और पहचान संबंधी विवरण सुरक्षित रखने के बाद दफना दिया गया है। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, ज्ञापन... आंदोलनजीवी बनता जा रहा जिला

जागरूकता की अलख या प्रशासनिक ढांचे के निठल्लेपन से उपज रही स्थिति

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

देश के साथ-साथ अब मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली और ज्ञापनों की पिछले कुछेक माह में जैसे बाढ़ सी आ गई है। वैसे तो देश के कौने-कौने में तरह-तरह के आंदोलन देखने और सुनने को मिल रहे है। राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे यह आंदोलन कहीं न कहीं सरकार की कार्यकुशलता पर प्रश्नचिन्ह लगाते दिखाई दे रहे है। देश भर में हो रहे आंदोलनों में अधिकतर की स्थिति यह है कि, सरकार को आंदोलनकारियों के सामने झुकते ही देखा जा रहा है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि, कौन सा आंदोलन कितना सही और कितना गलत है। लेकिन देश में सत्ता में बैठी भाजपा की सरकार लगातार बेकफुट पर नजर आ रही है। पिछले दशकों में ऐसा शायद पहली बार ही नजर आ रहा है कि, देश भर में आंदोलनों के जरिए सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार घेरा बंदी की जा रही है। आंदोलनकारी काफी हद तक सरकार को टक्कर देने में कामयाब भी हो रही है और सरकार मांगों को लेकर लगातार झुकती भी दिखाई दे रही है। यह स्थिति लगभग पूरे देश भर में लगातार देखने को मिल रही है।

इसी क्रम में मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे आदिवासी बाहुल जिले में भी पिछले कुछ महीनों में इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। जिले के आदिवासी, किसान, विद्यार्थी और राजनीतिक दल अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर लगातार जिला मुख्यालय पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखते दिखाई दे रहे। सभी मामलों में उम्मीद अब यही दिखाई दे रही है कि, इस तरह के धरनों, आंदोलनों, प्रदर्शनों के जरिए ही मांगे मनवाई जा सकती है। इस तरह के आयोजनों से परिणाम भी निकलकर सामने आ रही है तो कईयों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। यहां यह कहना भी गलत नहीं होगा कि, देश में चल रही उथल-पथल का सीधा असर अब झाबुआ जिले में भी देखने को मिल रहा है। या यह भी कह सकते है कि, देशभर के आंदोलन और प्रदर्शनों को देखते हुए जिले की जनता भी अब जागरूक हो रही है और अपने हक, अधिकार को लेकर किस तरह की मांगे मनवानी है यह समझ चुकी है। प्रेरणा चाहे जहां से मिली हो लेकिन जिले की आदिवासी जनता अब देखादेख ही सही लेकिन उस धारा से जुड़ने की कोशिश कर रही है जो वह अब तक वंचित दिखाई दी है।

जिले में हो रहे इस तरह के आंदोलनों और प्रदर्शनों से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि, ठेठ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के सरकारी दावे अब भी जिले में फिसड्डी ही साबित हो रहे है और इन सब का एक सीधा कारण है जिले में नौकरशाही के निठल्लेपन का बोलबाला। वैसे तो जिले में कई समस्याएं है। जिलेवासी अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए दो-चार हो रहे है। जन समस्याओं का स्तर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि, प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाईयों में आवेदनों की संख्या घटने की जगह लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अधिकारियों के रवैये ऐसे है जैसे उन्होने इस जिले को पूरी तरह तार दिया हो ओर चारों और विकास की गंगा बहा दी है लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट जिले में दिखाई दे रही है। छोटे-छोटे इवेंट कर उन्हे बड़ी-बड़ी उपलब्धियों में गिनाना, अखबारों में छपवाना, इलेक्ट्रानिक मीडिया में वक्तव्यों से छा जाना जिले के आला ही नहीं अदना अधिकारियों की भी प्रवृत्ति बनता जा रहा है। लेकिन आमजन की समस्या जस की तस दिखाई दे रही है और यही वह वजह है जिसने जिलेवासियों को मजबूर कर दिया है कि, वे अब अपनी समस्याओं और मांगों के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली और ज्ञापनों के जरिए ही अपनी समस्या जिम्मेदारों के सामने रख रहे है। पिछले कुछ महीनों में जिला मुख्यालय पर इस तरह आंदोलनों और प्रदर्शनों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही दिखाई दिया है और आगे भी यही उम्मीद है कि, यह और अधिक बढ़ेगा।

जिले के किसान दुरूस्थ अंचलों से पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय की सड़कें माप रहे है। पिछले कुछ दिनों में किसानों के कई जत्थे जिला मुख्यालय पहुंचे है। कभी कोई 60-65 किलोमीटर की जिले की सड़क मापते हुए फसल बीमा के भुगतान के लिए जिला मुख्यालय पहुंचता है। तो कभी इतनी ही दूरी तय कर किसान भूमि अधीग्रहण के सही मुआवजे के लिए आंदोलन करता दिखाई दे रहा है। झाबुआ के इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ कि किसान, रोड़ निर्माण में जा रही अपनी जमीन के सही मुआवजे के लिए जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रोरेट कार्यालय में लगातार पांच दिनों तक धरने पर बैठे रहे। हालांकि प्रशासन ने इनकी मांगे मानने में असमर्थता जता दी थी। बावजूद इसके किसानों ने जिला कलेक्टर और अधिकारियों को उनके कर्तव्य याद दिलाकर अपना धरना लगातार जारी रखा। प्रशासनिक लचरता को भांपते हुए किसानों ने प्रशासन को सख्त और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तब जाकर प्रशासन ने भोपाल में बैठी सरकार से किसानों का सीधा संवाद करवाया। हालांकि बात अब भी आश्वासन पर ही टीकी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि, जो काम प्रशासन ने किसानों के धरने के पांचवें दिन किया वही काम शायद धरने के दूसरे दिन भी हो सकता था, लेकिन तब नौकरशाही अपने पूरे रूबाब पर थी और किसानों को यह कह दिया गया था कि, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।

दो-चार बड़े आंदोलनों को हटा भी दें तो जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रोरेट कार्यालय में आए दिन कोई न कोई हंगामा आसानी से देखने को मिल रहा है। कभी जिले के आदिवासी अपनी पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंच रहे तो कभी कोई राजनीतिक संगठन जिले की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन दे रहे है। कहीं राशन नहीं मिल रहा है तो कहीं अव्यवस्थाओं का अंबार है। कहीं स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर क्या स्टॉफ ही मौजूद नहीं है तो कहीं सरकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी छोड़ अपने प्रायवेट क्लिनिक संचालित करते दिखाई दे रहे है। जिलेवासियों के पास समस्याएं बहुत है और उनका निराकरण प्रशासन उस गति से नहीं कर पा रहा है जैसा होना चाहिए। इसीलिए जिला मुख्यालय पहुंचकर आंदोलन, धरना और ज्ञापन देने जैसे रास्ते जिलावासी चुन रहे है। यह सिलसिला लगातार जिला मुख्यालय पर जारी है और आने वाले दिनों में भी इस तरह के आयोजन जिला मुख्यालय पर देखने को मिल सकते है।

सोशल मीडिया पर आने वाले दिनों में कलेक्ट्रोरेट पैदल मार्च कर अपनी समस्या के सामाधान के लिए कई कॉल और सूचनाएं आसानी से देखने को मिल रही है। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आने वाले मंगलवार को मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा है। जलवायु प्रदुषण को लेकर इस क्षेत्र के लोग लगातार कई वर्षों से परेशान होते दिखाई दे रहे है। कई बार आंदोलन और धरना प्रदर्शन इसे लेकर देखा गया है। कई शिकायतें इसे लेकर जिला प्रशासन को की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र से हो रहे जलवायु प्रदुषण को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दिया है। जिला प्रशासन की यही निठल्ली कार्यप्रणाली अब जनआक्रोश का कारण बनती जा रही है। आने वाले दिनों में मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र के प्रदुषण को लेकर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है।

जिले में जो आंदोलन पिछले कुछ समय में हुए है और आने वाले समय में होने वाले है उनका सीधा सा मतलब यह समझ आता है कि, जिले में आमजन समस्याओं से ग्रसित है और वे अपनी समस्याओं का हल चाहते है। दूसरी ओर जिला प्रशासन और उसका निठल्लापन है जो आजादी के 8 दशक बाद भी जिलेवासियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं तक नही पहुंचा सका है।

हर बार की तरह इस बार भी माथा उतारनी ही साबित होगी अतिक्रमण हटाओ मुहिम

जिला प्रशासन और नगरपालिका के पास नहीं है कोई स्थाई हल

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला मुख्यालय की नगरपालिका की अतिक्रमण मुहिम हमेशा से ही विवादों में रही है। हालांकि कहने को तो नगरपालिका की इस अतिक्रमण हटाओ मुहिम का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करना और आम नागरिकों को लगने वाले जाम से राहत पहुंचाना है। लेकिन अतिक्रमण की यह मुहिम अब तक नगरपालिका और जिला प्रशासन के लिए बस माथा उतारनी ही साबित हुई है। जब-जब जिला मुख्यालय पर नगरपालिका और जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने उतरता है वह केवल रटे-रटाए रूट पर ही काम करता दिखाई देता है मानों सारी की सारी समस्या सिर्फ इसी जगह पर हो। जबकि शहर के अन्य क्षेत्रों खास कर मुख्य बाजार में अतिक्रमण की स्थिति भयावह से भयावह होती जा रही है।

मंगलवार को एक बार फिर नगरपालिका और जिला प्रशासन का अमला ऐसी ही माथा उतारनी के लिए निकल पड़ा अपनी जेसीबी और लवाजमें के साथ। यह कोई पहला मौका नहीं है जब नगरपालिका और जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाओ मुहिम चला रहा है। पिछले कई सालों से नगरपालिका और जिला प्रशासन की इस अतिक्रमण मुहिम का कोई सफसफा आजतक स्थाई समाधान के तौर पर निकलकर सामने नहीं आया है। लगभग हर तीसरे-चौथे महीनें नगरपालिका और जिला प्रशासन इस तरह की अतिक्रमण मुहिम चलाता है और देखते ही देखते स्थिति ढाक के तीन पात हो जाती है। अफसोस इस बात का है कि, जिस दिन नगरपालिका प्रशासनिक लवाजमें के साथ इस मुहिम को अंजाम देता है उसके महज कुछ दिन बाद ही स्थिति पहले जैसी हो जाती है और समस्या का समाधान निकलने के बजाए स्थितियां और अधिक विकट दिखाई देने लगती है।

नगरपालिका की इस अतिक्रमा मुहिम पर हमेशा से ही सवाल खड़े होते नजर आए है। कारण यह है कि ले-देकर नगरपालिका, बस स्टेंड से विजय स्तम्भ तक ही अतिक्रमण हर बार हटाती है। इसके अलावा नगर के किसी भी अतिक्रमण से नगरपालिका या जिला प्रशासन को कोई लेना-देना नहीं है। नगरपालिका की इस कार्रवाई का हमेशा से ही विरोध होता आया है।

अतिक्रमण मुहिम में निशाना बने लोगों का कहना है कि, शहर के अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती है, ले-देकर सिर्फ इसी मार्ग पर नगरपालिका को अतिक्रमण क्यों नजर आता है। जबकि पूरा शहर ही अतिक्रमण की जद में है।

हालांकि यह भी सही है कि, अतिक्रमण के कारण इसी मार्ग पर सबसे अधिक परेशानी होती है क्योंकि बसों और बड़े वाहनों को नगर में प्रवेश के लिए इसी मार्ग का उपयोग होता है। अतिक्रमण के कारण दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। कई दुर्घटनाएं इस मार्ग पर हो भी चुकी है जिसमें लोगों के घायल होने के साथ ही जन हानी भी हो चुकी है। मगर इस समस्या के समाधान के रूप में नगरपालिका और जिला प्रशासन के पास कोई ठोस स्थाई समाधान अब तक नहीं है। पिछले कई वर्षों में नगरपालिका इस मार्ग से दर्जनों बार अतिक्रमण हटा चुकी है लेकिन समस्या है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कारण यह कि, नगरपालिका और जिला प्रशासन के पास इसका कोई स्थाई समाधान ही मौजूद नहीं है।

अतिक्रमण मुहिम का बार-बार शिकार होते लोगों का कहना है कि, नगरपालिका और प्रशासन इसका स्थाई समाधान निकाले और हमें कहीं ओर काम धंधा करने के लिए जगह उपलब्ध कराए, लेकिन पिछले कई वर्षों में नगरपालिका इस तरह के समाधान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जबकि नगर का मुख्य मार्ग इससे भी बुरी स्थिति में है और पूरे बाजार में अतिक्रमण की भरमार है, लेकिन नगरपालिका और प्रशासन शहर के मुख्य मार्ग के अतिक्रमण पर कभी नजर उठाकर भी नहीं देखता। और तो और नगरपालिका खुद भारी भ्रष्टाचार कर सिद्धेश्वर मार्ग पर अतिक्रमण कर गुमटियां बैचती है। जिससे इस मार्ग पर भारी जाम की स्थिति बनती है। मगर वहां किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। थांदलागेट सब्जी मंडी में भी स्थिति भयावह है लेकिन नगरपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों की अंधी आंखों को वह दिखाई नहीं देता। हर बार हम गरीबों की दुकानों को ही निशाना बनाया जाता है और हर बार हमें अतिक्रमण के नाम पर हजारों का नुकसान पहुंचाया जाता है।

बुधवार को नगरपालिका द्वारा एक बार फिर बस स्टेंड से लेकर विजय स्तम्भ तक अतिक्रमण मुहिम चलाई गई। लोगों की दुकानें और गुमटियां हटवाई गई। पक्की दुकानों के शेड तोड़े गए। लेकिन सवाल अब भी वहीं के वहीं खड़ा है कि, क्या अब आगे से इस मार्ग पर अतिक्रमण नहीं होगा...? या एक बार फिर नगरपालिका और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम के नाम पर माथा उतारनी कर ली है और गरीबों के गले नख दिया है...?

अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एसडीएम से लगाई गुहार

माही की गूंज, बामनिया।

ग्राम के मुख्य चौराहे पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम के कारण आम जन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन या कई बार दिन तीन से चार बार नगर की यातायात व्यवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि वाहन चालकों आधे आधे घंटे जाम में फसकर परेशान होना पड़ता है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से सराहनीय प्रयास किए गए थे ओर मुख्य चौराहे से सब्जी के ठेले हटवा दिए गए थें, लेकिन ये प्रयास भी नाकाफी साबित हुवे। वही स्थानीय पुलिस बल से ट्रैफिक व्यवस्थाओ के सुधार के लिए कोई आवश्यक प्रयास नहीं किए जाते, कई बार जाम की स्थिति बनने पर लोग पुलिस को सूचना देकर बुलाते है तब कही चौकी से एक जवान आता है। इस मामले में नगर युवा लवेश मुथा आगे आए ओर इस समस्या को लेकर एसडीएम राजस्व रितिका पाटीदार को आवेदन देकर ग्राम की बिगड़ती स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए, नगर की यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है।

शिव पार्वती विवाह धूमधाम से मनाया

माही की गूंज, सारंगी।

श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान योग कथा के तृतीय दिवस शिव पार्वती विवाह धूमधाम से मनाया गया। आयोजक बाबूलाल पाटीदार परिवार एवं नगर के भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा वाचक संत श्री बालकृष्ण नागर ने राजा परीक्षित सुखदेव संवाद, सुखदेव जन्म जैसा कलयुग से मुक्ति के दिव्य उपायो का माध्यमिक वर्णन किया। नागर जी ने कहा कि, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के मानसिक तनाव, मोह, लोभ ,क्रोध और भौतिक आकर्षणों में उलझता जा रहा है ऐसे समय में भगवान के नाम का स्मरण सबसे सरल, शहद और कल्याणकारी मार्ग है। कथा के दौरान मधुर भजन और धार्मिक गीतों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे।

साक्षरता पखवाड़े का आगाज

माही की गूंज, झाबुआ।

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार जिले में 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में साक्षरता पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। जिला, संकुल एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न जागरूकता एवं साक्षरता गतिविधियां आयोजित होंगी।

पखवाड़े के दौरान वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर असाक्षर व्यक्तियों का घर-घर जाकर चिन्हांकन, ऑनलाइन पंजीयन एवं अंकसूची वितरण किया जाएगा। साथ ही अक्षर साथियों का पंजीयन, साक्षरता कक्षाओं का संचालन एवं सामाजिक चेतना केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विभागों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के साथ बैठकें और कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी।

साक्षरता अभियान को जनअभियान का रूप देने के लिए छात्र-छात्राओं के सहयोग से साक्षरता रैली, साइकिल रैली, प्रभात फेरी एवं नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा नारा लेखन, चौपाल एवं जागरूकता शिविरों के माध्यम से शिक्षा और साक्षरता के महत्व का प्रचार किया जाएगा।

कमजोर बारिश होने से फसलों में इल्ली का खतरा, फलिया और दानों पर पड़ेगा असर

माही की गूंज, पेटलावद।

बारिश की बेरुखी ओर तेज धूप से सोयाबीन सहित अन्य फसलो को इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। जब फलियों में दाने भरने की शुरुआत होती है, तब पौधों को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इस समय पानी की कमी से दानों का आकार छोटा रह सकता है और पैदावार घट सकती है।

पेटलावद क्षेत्र में फसलों के अनुरूप बारिश नहीं होने से किसान उदास हो रहे हैं। पानी की कमी के कारण सोयाबीन की फसल भी सूखने लगी है। सोयाबीन की फसल में इल्लियों का कहर भी झेलना पड़ रहा है। किसानों ने खेतों में फसल की बुवाई करने को लेकर खाद-बीज उधार लेकर बुआई की थी। किसानों ने बताया कि बारिश नहीं होने के चलते फसलें सूख कर पीली पड़ने लगी हैं। गत वर्ष भी ज्यादा बारिश के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई थी, अब बारिश न होने से नुकसान हो रहा है। बारिश नहीं होने से किसानों के सामने फसल बचाने की समस्या पैदा हो रही है। बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन की फसल के सबसे ज्यादा नुकसान होने का खतरा है।फूल और फलियों पर इसका असर दिखने लगा है। सोयाबीन की फसल खराब होने से किसानों को ज्यादा नुकसान होगा। क्षेत्र में बीते सावन माह में से क्षेत्र में तेज बरसात नहीं होने के चलते किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते पूरे माह में सुबह शाम हल्की बारिश हुई थी। इनसे फसलों को मामूली राहत तो मिली, पर अभी और बारिश की जरूरत है। खेतों में गर्मी के चलते फसलों में कीट का प्रकोप बढ़ गया है। कई खेतों में इल्ली इतनी अधिक है कि किसानों को इसका कोई हल नहीं समझ आ रहा। कई किसानों के खेतों में समय पर कीटनाशक दवाइयां होने के चलते कीट का प्रकोप कम नजर आ रहा है। इल्ली प्रकोप होने के चलते सोयाबीन की फसल में अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है। इन खेतों में पत्तों को पूरी तरह से कीट प्रकोप ने छेद दिया। वहीं कई खेतों में सोयाबीन की फली को इल्ली ने नष्ट करना शुरू कर दिया है। इसके चलते किसने को नुकसान अधिक हो रहा है। किसानों का मानना है कि अगर समय पर बारिश होती रहती है तो यह इल्ली पैदा नहीं होती। खेतों में उमस और गर्मी से कई प्रकार की बीमारियां फसलों को लग रही हैं।

पंचायत उप निर्वाचन : प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन वर्ष-2026 का कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जिले में 1 जिला पंचायत सदस्य, 1 सरपंच एवं 3 पंच पदों के लिए उप निर्वाचन होगा। जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमांक-06 में जनपद पंचायत राणापुर की संबंधित ग्राम पंचायतों में निर्वाचन होगा। वहीं जनपद पंचायत थांदला की ग्राम पंचायत पलासडोर में सरपंच तथा ग्राम पंचायत परवाड़ा के वार्ड क्रमांक-20 और दौलतपुरा के वार्ड क्रमांक-10 में पंच पद के लिए चुनाव होगा। जनपद पंचायत मेघनगर की ग्राम पंचायत रंभापुर के वार्ड क्रमांक-13 में भी पंच पद के लिए निर्वाचन होगा, जो अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है।

निर्वाचन प्रक्रिया को देखते हुए विकासखंड राणापुर, थांदला एवं मेघनगर के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्व में स्वीकृत अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं। शनिवार, रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

चुनाव प्रचार के लिए वाहन, आमसभा एवं जुलूस आदि की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दी जाएगी। साथ ही अस्त्र-शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संबंधित क्षेत्रों के शस्त्र लाइसेंस चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक निलंबित किए गए हैं। अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराने होंगे।

अंतिम यात्रा की मुश्किल भरी राह, करोड़ो के खेल में खुद का विकास

श्मशान घाट की सड़क, आखिर कहां अटक रही कार्रवाई?

माही की गूंज, सारंगी।
संजय उपाध्याय

ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की तस्वीरें आम है जहा से अंतिम यात्रा पर निकले व्यक्ति ओर उसको ले जाने वाले लोगों के लिए राह मुश्किल भरी होती है। लेकिन जब ये तस्वीरें ऐसे क्षेत्र से आती है जहा के लोग पड़े लिखे, सक्षम ओर वहा की ग्राम पंचायत साधन सम्पन्न ओर प्रयाप्त टेक्स वसूली होने के बाद भी आम जनता की मूल-भूत सुविधा को पूरा नहीं कर सकते तो फिर विकास की परिभाषा पर सवाल उठते है। जिस पंचायत में अवैध पट्टे के नाम पर करोड़ो की लेन-देन की चर्चा है वहा की श्मशान तक पहुंचने की सड़क की बदहाली से सवाल उठता है कि, जिम्मेदारों के विकास को ही आम जनता का विकास मान लिया जाए।

पाटीदार समाज के श्मशान घाट तक जाने वाले बदहाल मार्ग की समस्या को लेकर कई बार खबरे प्रकाशित हुइ, कई बार इसकी मांग की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई जमीन पर नजर नहीं आ रही है। लगातार खबरों के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया गया, फिर भी मार्ग की स्थिति जस की तस बनी हुई है।

बारिश के दिनों में मार्ग पर कीचड़ और गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है। इसी रास्ते से किसानों और ग्रामीणों का आना-जाना होता है तथा अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रही है। जबकि सीमेंट रोड के लिए अलग-अलग मदो से बजट आता है ,यह सवाल अब ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

क्या मामला स्वीकृति, बजट या विभागीय प्रक्रिया में अटका हुआ है? या फिर जिम्मेदारों को समस्या की पूरी जानकारी होने के बावजूद इसे नजरअंदाज किया जा रहा है? अब लोगों की मांग है कि, जिम्मेदार अधिकारी मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति देखें और यह स्पष्ट करें कि, श्मशान घाट मार्ग का काम आखिर कब शुरू होगा।

वीरान हुआ तहसील परिसर, आम जनता को उम्मीद खाली पड़ी भूमि पर कुछ नया होगा

नगर के सभी मुख्य सरकारी भवन अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे, बाजार भी हुआ सुना

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

कभी पेटलावद की नाक रहा तहसील न्यायालय परिसर अब वीरान हो चुका है इसके साथ ही वर्षों पुरानी चहल पहल भी यहां समाप्त हो गई है। पेटलावद विधानसभा के लिए बने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ओर तहसील न्यायालय परिसर नगर के सबसे व्यस्तम क्षेत्र में से एक रायपुरिया मार्ग, गांधी चौक पर अग्रेजों के शासन काल में बने भवन में चलते आ रहे थे। लेकिन सरकार ने इस स्थान पर नए भवन बनाने की जगह इन भवनों के लिए नए स्थान सुरक्षित कर नए भवन बनवा दिए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय तो पूर्व में ही यहां से नए भवन में रूपगढ़ रोड पर स्थानांतरित किया जा चुका था लेकिन तहसील भवन के निर्माण में देरी होने के चलते तहसील कार्यालय इसी परिसर में चल रहा है तहसील संबधी प्रकरणों को लेकर लोगों की आवाजाही लगी हुई रहती थी। लेकिन विगत दिनों में बचा तहसील कार्यालय भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया जिसके बाद पुराना भवन परिसर सुनसान इलाके में बदल गया है।

व्यापार हुआ प्रभावित

एसडीएम ओर तहसील न्यायालय के आसपास बड़ी संख्या में यहां से जुड़े व्यापार स्टेशनरी, ऑन लाइन, स्टाम्प वेंडर , फोटो कॉपी, चाय नाश्ते की दुकान, होटल, फोटो स्टूडियो जैसी कई दुकानें इन परिसर के माध्यम से चलती थी। लेकिन एक के बाद एक सरकारी भवनों के स्थांतरित होने से इस क्षेत्र का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो गया है। यहां तक कि कई दुकानदार तो सिर्फ इस परिसर से होने वाले व्यापार पर ही निर्भर थे उन पर बेरोजगार होने की स्थिति बन गई है ।

सिविल हॉस्पिटल भी जा चुका है

कुछ समय पूर्व इसी क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी था लेकिन सिविल हॉस्पिटल बना कर इसकी नई बिल्डिंग नगर से लगभग तीन किलोमीटर दूर बरवेट रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र की चहल पहल पहले ही खत्म हो गई थी। जबकि पुराने परिसर में भवन निर्माण हेतु पर्याप्त जगह थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते नए भवनों के निर्माण के लिए पुराने परिसर के जगह स्थानीय अधिकारियों ने नई जगह चिन्हित कर दिया। अब आम जनता को अस्पताल, एसडीएम कोर्ट , तहसील न्यायालय, सिविल न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पुलिस के कार्यालय नगर से दूर ओर अलग-अलग मार्ग पर बना दिए गए जिससे लोगों को भारी भजियत हो रही हैं। वही उक्त परिसर के अनैतिक कार्यों का अड्डा बनने के भी चर्चा शुरू हो गई है,यहां सुनसान ओर खाली पड़े परिसर का लोग गलत कार्यों के लिए उपयोग कर सकते है।

अस्थाई बस स्टेशन बनाया जाए

अब लोगों को खाली पड़ी इस लंबी चौड़ी शासकीय भूमि के नए सिरे से उपयोग की उम्मीद है। जिससे इस क्षेत्र ओर नगर की शान कहे जाने वाले सबसे व्यवस्तम क्षेत्र की दोबारा रौनक लौटाई जा सके । अभी नगर की सबसे ज्वलंत समस्या स्थाई बस स्टेशन की है जिसके नहीं होने से आम जनता ओर बसों में यात्रा करने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस स्टेशन की कमी के चलते यहां से चलने वाली कई बसे सड़क किनारे खडी की जाती है जो दुर्घटना का आए दिन कारण बन जाती है,यात्रियों के बैठने रुकने तक के लिए स्थान नहीं है। ऐसे में इस सुनसान पड़े परिसर का उपयोग फिलहाल अस्थाई बस स्टेशन के लिए किया जा सकता है। खास कर की रात में सड़क किनारे खड़े रहने वाले वाहनों को यहां खड़ा करने की अनुमति देकर काफी हद तक ट्रैफिक व्यवस्थाओ को भी सुधारा जा सकता है।

मंदिर से भगवान के चांदी के कड़े चोरी

माही की गूंज, बामनिया।

- हनुमान जी के दोनों पैरों से चांदी के कड़े ले गए चोर।

बामनिया के पेटलावद रोड स्थित मंशापूर्ण खेड़ापति मंदिर से चोरी की घटना सामने आई है। यहां अज्ञात चोरों ने मंगलवार की दोपहर को मंदिर को सुना देख, चोर मंदिर में घुसे और हनुमान जी की प्रतिमा के पैरों में पहने हुए चांदी के कड़े जिनका वजन लगभग तीन सौ ग्राम है चोर चुरा कर ले गए। चौंकाने वाली बात ये रही कि, चोरी की जानकारी मन्दिर पुजारी को बुधवार सुबह लगी जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच पंचनामा बना कर जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी अनुसार मंगलवार को नियमानुसार भगवान को चोला चढ़ाया गया, जिसके बाद की फोटो में भगवान के पैर में कड़े पहने हुए थे। रात्रि में मंदिर पर प्रति मंगलवार सुंदरकांड होता है उसका भी आयोजन हुआ लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। सुबह पुजारी ने जब भगवान की आरती की तब उनकी नजर भगवान के चरणों पर पड़ी, जहा पैर के कड़े गायब मिले। तथा रात्रि में सुंदरकांड के समय के खिचे गए फोटो को देखने पर भगवान के पैरो के कडे नही दिखे। जिस पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि, चोरो ने दोपहर के समय मंदिर के सुने होने ओर मंदिर के द्वार बंद होने का फायदा उठाया ओर चोरी को अंजाम दिया। गनीमत रही कि, भगवान की मूर्ति पर ओर भी चांदी के आभूषण और चांदी का छत्र लगा हुआ था वो चोर नहीं चुरा पाए।

धार्मिक स्थल पर हुई इस चोरी की खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। इससे श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि, चोरों में अब भगवान का भी डर नहीं रहा।

भादवा मास : भगवान नीलकंठेश्वर की शाही सवारी ने किया नगर भ्रमण

माही की गूंज, पेटलावद।

भादव मास के प्रथम सोमवार को पेटलावद नगरी का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। नगर के आराध्य देव और पेटलावद के राजा नीलकंठेश्वर महादेव राजसी ठाठ-बाट और पूरे लवाजमे के साथ नगर भ्रमण पर निकले। अपने आराध्य देव के स्वागत के लिए नगरवासी सुबह से ही उत्साह और श्रद्धा के साथ तैयार नजर आए। जैसे ही बाबा नीलकंठेश्वर की शाही सवारी नगर की गलियों में पहुंची। हर और हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। नीलकंठेश्वर भक्त मंडल के तत्वावधान में निकली इस भव्य शाही सवारी में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए थे। भगवान की पालकी पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर, पुष्प अर्पित कर और पुष्पवर्षा कर बाबा का अभिनंदन किया।

भक्ति में झूमे श्रद्धालु

नीलकंठेश्वर महादेव की पालकी को अपने कंधों पर उठाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ सी लग गई। विभिन्न समाजों के युवाओं ने एक जैसी वेशभूषा में पालकी को कंधा देकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। पालकी के साथ चल रहे भक्त भजन और जयघोष करते हुए नृत्य कर रहे थे। बैंड और ढोल की गूंज के बीच पूरा नगर भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। शाही सवारी में भगवान भोलेनाथ की आकर्षक झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं श्री राम मंदिर राममोहल्ला के बच्चों द्वारा प्रस्तुत अखाड़ा प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। युवाओं द्वारा प्रस्तुत तलवारबाजी, घोड़ी नृत्य और पारंपरिक प्रदर्शन ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। ढोल-बैंड की थाप पर नाचते-झूमते भक्तों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया।

रात 12 बजे मंदिर पहुंची सवारी

नगर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए भगवान श्री नीलकंठेश्वर महादेव की शाही सवारी देर रात लगभग 12 बजे पुनः मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भव्य महाआरती का आयोजन किया। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। महाआरती के साथ भगवान की शाही सवारी की विधिवत पूर्णाहुति हुई। दिन भर चले इस धार्मिक आयोजन ने पेटलावद को भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।

रक्षाबंधन के पूर्व लाखों की चोरी: पुलिस अब तक नहीं कर पाई चोरी का खुलासा

माही की गूंज, खवासा।

स्थानीय चौकी अंतर्गत ग्राम नौगावा नगला में बामनिया-तलावड़ा मुख्य मार्ग पर 8 लाइन के समीप स्थित दुकान-घर की खिड़की तोड़ सेंध लगाकर चोरों ने रक्षाबंधन के पूर्व रात्रि में नगदी एवं जेवरात की लाखों की चोरी को अंजाम दिया।

नौगांवा नगला में शंकरलाल भटेवरा के नाती सौरभ पटेल के मकान में रक्षाबंधन के पूर्व रात्रि में चोटों ने खिड़की में सेंध लगाकर उसे तोड़कर दुकान व घर के अंदर घुसे चोट्टों ने आराम से दुकान के गले को खंगाला एवं घर के अंदर सभी अलमारी-तिजोरी एवं पलंग को खंगाल कर सभी सामान बिखेर कर बड़ी चोरी को अंजाम दिया।

मामले में खवासा चौकी प्रभारी अनिल सिंह गहुरिया ने बताया कि, राखी के पूर्व रात्रि में नौगांवा नगला में जो चोरी हुई थी उसका मामला दर्ज कर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है।

साहब कितने की चोरी हुई है...? जिस पर साहब ने जवाब दिया कि, चोरी हुई है और उसका खुलासा करने में पुलिस जुटी है पर साहब ने चोरी कितने की हुई और क्या-क्या चोरी गया बताने से बचते रहे। यानी तय हे पुलिस ने यहां भी जो-जो चोरी हुआ उसका पूरा उल्लेख अभी तक मामले में दर्ज नहीं किया होगा। इसलिए चोरी का आंकड़ा बताने में साहब बचते रहे।

जब मामले में सौरभ के मामा मनोज भटेवरा से बात की तो बताया, राखी के पूर्व रात्रि में चोट्टों ने बड़ी चोरी को अंजाम हमारे घर में दिया है। चोरी की घटना के दिन बहू राखी करने मायके गई थी तो सौरभ पहली मंजिल पर ऊपर सोया था। चोट्टों ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और घर व दुकान में रखी सारी नगदी अनुमानित 7 लाख व 50 ग्राम सोने का बिस्किट अन्य सोने की रकमें व चांदी की रकमें करीब 30 लाख के लगभग की बड़ी चोरी को अंजाम चोट्टों ने दिया है।

भटेवरा ने बताया कि, सौरभ जब सुबह 6 बजे उठकर नीचे आया तो चोरी होने का पता चला जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर एसडीओपी साहब के साथ डॉग स्क्वायड एवं पूरा पुलिस बल आया था लेकिन चोटों का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है।

गूंज खबर के बाद रन्नी पहुची जांच टीम

माही की गूंज, खवासा।

पिछले अंक में माही की गूंज में ''सरपंच पति ने शासकीय तालाब बनाने के नाम पर निजी पट्टे वाली भूमि पर किया अवैध खनन''शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें निजी पट्टेवाली भूमि से तालाब के नाम पर मोरम की खुदाई करने का मामला सामने आया था। जिसका आरोप रंन्नी के सरपंच पति अशोक झोड़िया पर था। ग्रामीणों ने आपत्ति लेते हुए वीडियो बनाने के साथ प्रशासन को भी शिकायत की थी। तथा माही की गूंज में समाचार के प्रकाशन के बाद त्वरित थांदला जनपद से राजस्व पटवारी व सब इंजीनियर की टीम बनाई गई। तथा गुरुवार को ही ग्रामीणों को लेकर मौके पर जाच टीम पहुंची। जहां पटवारी ने आपत्तिकरता ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद सैटेलाइट ऐप मोबाइल कैमरे से उनकी जगह को देखा। जिसमें 12 आरा मे निजी जमीन पर खुदाई तालाब बनाने को लेकर कर दी। हालाकी तालाब जहां बना है वहां 160 खसरा न पर बनाया गया है। और जहां मोरम की खुदाई की गई है वह 163 खसरा नंबर पर है। जो वहां के स्थानीय ग्रामीणों के नाम पर रजिस्टर्ड है। मौके पर राजस्व विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के सब इंजीनियर ने पंचनामा बनाया। पंचनामा बनाने के बाद रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।

ग्रामीणों का कहना है कि, हमारे खेत में जो खुदाई करी उसकी भरपाई ग्राम पंचायत करें और इस तरह से कहीं दूसरी और ऐसी खुदाई भी ग्राम पंचायत नहीं करें जो विवाद का कारण बने। वही सरपंच प्रतिनिधि अशोक जोड़िया ने मौके पर रहकर ग्रामीणों को आश्वास्त क्या कि, आपकी जगह पर जहां खुदाई कर दी गई है वहां का आपको जो भी भरपाई होगी ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी तथा आपकी जगह को समतल कर दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत के सब इंजीनियर नवलसिंग बडोले ने बताया कि, हम मौके पर गए थे। और जांच की थी 12 आरा निजी जमीन पंचायत ने खुदाई कर दी थी। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वहां के ग्रामीणों को ही सिंचाई के लिए तालाब का पानी मिल पाएगा। हमने मौके पर पंचनामा बनाया है और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। जो भी आदेश होगा वह वरिष्ठ अधिकारी ही इस पर निर्णय ले पाएंगे।

वायरल बुखार का प्रकोप, सरकारी ओर निजी क्लिनिको में मरीजो की भीड़

-निजी क्लीनिक के बहार लगी मरीजों की भीड़।

-लेब पर जांच के लिए लगी भीड़।

माही की गूंज, पेटलावद।

बदलते मौसम के चलते इन दिनों बीमारी का भारी प्रकोप फैला हुआ है। ग्रामीण ओर शहरी इलाकों से वायरल बुखार के मरीज सरकारी ओर निजी क्लिनिकों पर बड़ी संख्या में इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे है। आलम ये है कि, मरीजों के लिए बेड तक नहीं मिल रहे है; लोग डाक्टरों के क्लीनिक के बहार बड़ी संख्या में खड़े दिख रहे है, वही पैथोलॉजी सेंटर पर भी लोगों की जांच करवाने और दवाई की दुकानों पर भी भीड़ जुटी हुई है।

शरीर में कमजोरी

वायरल बुखार के बढ़ते प्रकोप से लोगो को परेशान होना पड़ रहा है, घरों में एक-दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार सहित लोग वायरल बुखार से बीमार हो रहे है। वायरल बुखार से शरीर में अकड़न, थकावट, गले की खराबी हो रही है। वायरल बुखार के प्रकोप तीन से चार दिन मरीज को ठीक होने में लग रहे हैं। जांच में वायरल बुखार सहित मलेरिया की भी रिपोर्ट आ रही है।

रहे कोरनटाइन, ऐसे करे बचाव

इस संबंध में जब एक्स्पर्ट से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि, ये भी एक तरह का वायरस है। जिससे बचाव बेहत जरूरी है ओर ये कोरोना की तरह एक से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। हालांकि ये वायरस बेहद खतरनाक नहीं होता है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। इससे बचाव के लिए बाजार के खाने से बचे, अपने आस पास साफ सफाई रखे, मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग करे। सर्दी खासी होने पर भीड़-भाड़ से दूर रहे, बीमार होने की दशा में बच्चो को स्कूल नहीं भेजे ओर बीमार होने पर तुरंत डाक्टर से संपर्क करे।

संपादकीय

उम्मीद से ज्यादा तेज़ी

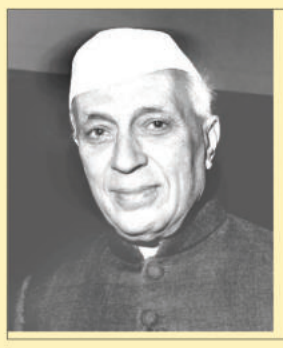

ऐसे वक्त में जब अमेरिका-ईरान युद्ध से कच्चे तेल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और आपूर्ति श्रृंखला बाधित रही, देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत सुखद ही कहा जायेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8 रही है। यह प्रदर्शन केंद्रीय बैंक आरबीआई के सात फीसदी की विकास दर के अनुमान से भी अधिक है। यह दर बाजार की उम्मीदों से भी अधिक है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव और ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। दरअसल, इस तेज विकास दर को पाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से मदद मिली है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र में दस फीसदी की विकास दर उत्साहजनक रही है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 तथा निर्माण क्षेत्र में विकास दर 7.7 फीसदी की वृद्धि ने देश की आर्थिकी को गति दी है। दरअसल,औद्योगिक विकास ने भी सकल विकास दर को संबल दिया । इससे भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था के महत्व का पता चलता है। उल्लेखनीय है इस दौरान देश में उपभोक्ता मांग अच्छी बनी रही। वास्तव में देश के बड़े उपभोक्ता बाजार ने वैश्विक मांग और व्यापार में आई शिथिलता के बावजूद स्वदेशी आर्थिकी को मजबूती दी है। भले ही देश का विपक्ष इस कामयाबी को आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है लेकिन सरकार इस उपलब्धि पर अपनी पीठ थपथपा सकती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर जारी अस्थिरता के चलते भविष्य में पैदा होने वाले जोखिम कम नहीं हो जाते हैं। विकास दर के इन आंकड़ों के चलते हमें लापरवाह होने से बचना चाहिए। पूंजीगत सामान के ज्यादा उत्पादन व सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि से पता चलता है कि देश में संरचनात्मक विकास व निवेश की मांग बनी हुई है।

वास्तव में देश के नीति-नियंताओं को हमारी खाद्य श्रृंखला को मजबूती देने वाले और महंगाई को प्रभावित करने वाले कृषि उत्पादन में तेजी लाने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बीच इस बार देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई असमान बारिश का असर भी कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। देश का कृषि क्षेत्र अभी भी मौसम की मार के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। बहरहाल, पहली तिमाही के उत्साहवर्धक आंकड़े देश की वार्षिक विकास की अनुमानित दर में संशोधन करने की जरूरत को बताते हैं। यदि देश में घरेलू मांग और निवेश मजबूत बने रहते हैं तो हमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक विकास दर का 6.7 फीसदी का अनुमान कम लग सकता है। इसके बावजूद, एक अच्छे तिमाही नतीजों का मतलब यह नहीं है कि आसन्न जोखिम से पूरी तरह बचा जा सकता है। ध्यान रहे कि 7.8 फीसदी की विकास दर पिछली तिमाही की 8.6 फीसदी की वृद्धि दर के मुकाबले थोड़ा कम है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी अनिश्चितताएं अभी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। वैश्विक कारोबारी तनाव, भू-राजनीतिक टकराव और ऊर्जा आपूर्ति में लगातार जारी संभावित बाधाओं से हमारा लागत मूल्य बढ़ सकता है। जिससे देश के निर्यातों में वृद्धि की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं। भारत जैसे देश के लिये कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जो अपने अधिकांश ऊर्जा संसाधनों का आयात करता है। जरूरी यह भी है कि देश की विकास दर में दर्शाई जा रही तेजी का अहसास आम आदमी की जिंदगी में भी दिखायी दे। देश की आंतरिक स्थितियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। विकास दर वृद्धि के सम्मोहन में देश में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या की अनदेखी नहीं की जा सकती। बहरहाल, जहां सरकार विकास दर को सुधारों का प्रतिफल बता रही है, वहीं विपक्ष जीडीपी के अनुमानों के तरीकों पर सवाल उठा रहा है। ऐसी जांच-पड़ताल व बहस ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। बहरहाल, सरकार को विकास दर के आंकड़ों से आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि विकास के आंकड़ों को व्यापक विकास में बदला जाए। जिससे सही मायने में रोजगार बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े और हम आसन्न वैश्विक संकटों का मुकाबला करने में सक्षम हों।

नीट परीक्षा के आयोजन में मौजूद बुनियादी खामियां

नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) के साथ समस्या सिर्फ़ इसके पेपर लीक होने की प्रवृत्ति नहीं है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि इसके काम का तरीका बहुत अपरिष्कृत है। इसके लिए जो ऊंचा लक्ष्य रखा गया है, वह इसके अंदरूनी पुराने तौर-तरीकों से मेल नहीं खाता। नीट का मकसद लाखों लोगों में से उन्हें चुनना है, जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने को सबसे योग्य हों।

वास्तव में, इस मुश्किल काम को पूरा करने का तरीका बहुत सामान्य सा है। इसमें तीन विज्ञान विषयों–भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान–से 180 सवाल पूछे जाते हैं। ये सभी सवाल एक ही फॉर्मेट में होते हैं। हर सवाल के लिए चार संभावित जवाब दिए जाते हैं। उनमें से सिर्फ़ एक सही होता है। माना यह जाता है कि अगर छात्र होशियार है, तो वह तुरंत सही जवाब पहचान कर उसे चिह्नित कर देगा और अगले मल्टीपल-चॉइस क्वेश्चन (एमसीक्यू) पर बढ़ जाएगा। इसी फ़ॉर्मेट को एमसीक्यू कहते हैं।

यह फ़ॉर्मेट भारतभर में इतना क्यों फैल गया है, यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब ढूंढ़ना वाजिब होगा। बैंकिंग से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक, लगभग हर क्षेत्र में अब शिक्षा और नौकरी के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए एमसीक्यू सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यह इतना पसंदीदा क्यों बन गया है?

एक तो, एमसीक्यू के ज़रिए बड़े पैमाने पर परीक्षा लेना और तैयारी करवाना आसान होता है। कोचिंग उद्योग अब शिक्षा से भी बड़ा वित्तीय कारोबार बन गया है और इस उद्योग को एमसीक्यू बहुत भाता है। यह सिस्टम मशीनी तरीके से नंबरों का आकलन करने के लिए भी सुविधाजनक है। इस तरह की मार्किंग में निष्पक्षता दिखती है। पेपर लीक होने की घटनाओं को छोड़ दें, तो लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता पक्षपात की होती है; इसलिए अगर कोई तरीका इस समस्या को दूर करता हो, तो उसकी लोकप्रियता कम करना मुश्किल होता है।

असल में, एमसीक्यू-आधारित परीक्षा प्रक्रिया की मार्फ़त बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की छंटाई कर उन्हें बाहर करना आसान बन जाता है। चूंकि बाहर किए जाने की यह प्रक्रिया मशीनी होती है और इसलिए निष्पक्ष बन जाती है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया को वैध माना जाता है, भले ही यह पूरी सटीक न हो।

वैधता और सटीकता के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। 'वैधता' का मतलब है लोगों की सोच में और कानूनी तौर पर सही उतरना। दूसरी ओर, 'सटीकता' का मतलब है परीक्षा के तरीके का उसके उद्देश्य से गहरा संबंध होना। नीट के खास संदर्भ में, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि जो छात्र तेज़ी से भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल कर सकता है, उसमें एक अच्छा डॉक्टर बनने की क्षमता और योग्यता, दोनों हैं। नीट का काम बस बड़ी संख्या में आवेदकों को छांटकर अलग करना है। छंटनी के बाद बाहर हो चुके छात्रों में कितनों में डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी गुण और क्षमता थी, इसकी किसी को परवाह नहीं है। इस बात की भी कोई परवाह नहीं करता कि बाहर किए गए छात्र समाज के कमज़ोर वर्गों से थे या नहीं। ज़्यादातर मामलों में, नीट और ऐसे ही दूसरी परीक्षाओं में सफलता कोचिंग से जुड़ी होती है। कोचिंग पर उम्मीदवार और उनके माता-पिता का काफ़ी पैसा खर्च होता है। बहुत से छात्र किसी भी तरह की कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, अच्छे और नामी कोचिंग सेंटर्स की तो बात ही छोड़ दें; ये सेंटर्स अपनी सफलता की दर, अपने कोच और वहां रहने-सहने की सुविधाओं के प्रचार-प्रसार पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। अत्यंत व्यावसायिक हो चुकी इन सेवाओं ने स्कूलों और शिक्षकों को अप्रासंगिक बना दिया है।

नीट में हालिया पेपर लीक का मामला कोई इक्का-दुक्का घटना नहीं थी। असल में, यह इतना आम हो गया है कि अगर कोई परीक्षा बिना पेपर लीक हुए भी हो जाए, तब भी लोगों में शक बना रहता है। प्रश्नपत्र लीक होने से परीक्षा का मकसद ही खत्म हो जाता है; साथ ही, यह उस सामाजिक माहौल को भी खराब कर देता है, जिसमें युवा रहते हैं और परीक्षा में सफल होने के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं। प्रश्नपत्र पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं, और न ही यह धांधली का एकमात्र तरीका है, जिससे भारत की परीक्षा प्रणाली दरपेश है। धांधली का मुख्य तरीका पेपर लीक बनने से बहुत पहले, गलत ढंग से सफलता पाने की कहानियां आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में आम चर्चा का विषय हुआ करती थीं।

सवाल हल करने में मदद करने वाली कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में साथ ले जाना मना था, लेकिन यह चलन इतना आम था कि इसने रवींद्रनाथ टैगोर तक का ध्यान खींचा। एक दिलचस्प जक्रि में, हैरान कविवर ने ऐसे छात्रों की तुलना हनुमान से की थी, जो लक्ष्मण की जान बचाने वाली खास जड़ी-बूटी लाने की बजाय पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे।

आज़ादी के बाद वाले काल में और डिजिटल दौर से पहले, परीक्षा से जुड़ी कई अन्य किस्म की धांधलियां सामने आईं। एक थी, 'परीक्षा केंद्रों की बिक्री', जहां उम्मीदवार आसानी से सीधे पाठ्यपुस्तक या उसकी 'कुंजी' (सवालों के हल आसान तरीके से समझाने वाली पुस्तिका) जैसे भरोसेमंद स्रोतों से जवाब नकल कर लिख देते थे। 'नीलाम किए गए' ऐसे कुछ परीक्षा केंद्रों में वे लोग भी मदद के लिए होते थे, जो ब्लैकबोर्ड पर सही जवाब लिख देते थे। वहीं कुछ जगहों पर छद्म परीक्षार्थी (असली उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने वाले) की सुविधा भी मिलती थी, जिनका ज्ञान घबराए हुए परीक्षार्थी से कहीं ज़्यादा होता था।

हालांकि, नकल करने और पेपर लीक होने के बीच बुनियादी फ़र्क है। पेपर लीक होना न सिर्फ़ व्यवस्था की नाकामी बल्कि उसके नैतिक ढांचे के पतन का भी संकेत है। पेपर लीक होने की खबर सुनकर उम्मीदवार को लाचारी महसूस होती है-न्याय पाने के अपने हक का उल्लंघन हुआ देखकर। जब पेपर लीक होना आम बात हो जाए, तो शक बन जाता है कि जिस प्रश्नपत्र को कोई उम्मीदवार हल कर रहा है, उसके बारे में कुछ लोगों को अवश्य ही पहले से पता है व उन्हें इस 'पूर्व-पहुंच' का फ़ायदा मिलेगा।

कृष्ण कुमार

इस साल नीट को रद्द कर दिया गया (और बाद में दोबारा कराया गया), क्योंकि पेपर लीक को छिपाना नामुमकिन हो गया था। पिछले साल, कानूनी दांव-पेच से परीक्षा रद्द होने से तो बच गई, लेकिन सीमित पुनर्परीक्षा ने लीक के पैमाने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस साल परीक्षा रद्द होने के बाद हुई आत्महत्याओं से हमें हैरान नहीं होना चाहिए- ये बताती हैं कि 18 साल के आदर्शवादी युवाओं के मन को कितना आघात लगता है। नीट पेपर लीक का असर उन बहुत से युवाओं पर भी पड़ा, जिनका परीक्षा से कोई सीधा लेना-देना नहीं; लीक का मतलब सिर्फ़ व्यवस्था की कारगुजारी या आयोजन क्षमता में कमी नहीं, बल्कि उसके नैतिक चरित्र का संकट है।

नीट आयोजित करने के लिए चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल क्यों न हो, उसका अंदरूनी अपरिष्कृत कामकाजी ढांचा कायम रहेगा। तीन विज्ञान विषयों के पाठ्यपुस्तक-आधारित सवालों को सुपरसोनिक रफ़्तार से 'हल' करने की योग्यता का डॉक्टर बनने की प्रेरणा से लेना-देना कम ही है।

रफ़्तार की जरूरत कोचिंग संस्थानों को बहुत भाती है। वे युवाओं को गलत विकल्पों को पहचानने और सही जवाब ढूंढ़ने का प्रशिक्षण देते हैं। जबकि इस प्रदर्शन का सीखने या समझने की योग्यता से कोई वास्ता नहीं, और उस आनंद से तो कतई नहीं, जो शिक्षा ग्रहण करने पर मिलता है।

एआई युग में नौकरी मिलने-खोने के यक्ष प्रश्न

एआई को लेकर में सबसे बड़ा डर यही रहा है कि मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी। चैटबॉट से लेकर जनरेटिव एआई तक, तकनीक जिस तेजी से विकसित हुई है, उसने इस आशंका को और गहरा किया है।

वैश्विक वित्तीय संस्था नोमुरा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से अगस्त, 2026 के बीच भारत में एआई से संबंधित करीब 83,100 नौकरियां पैदा हुईं, जबकि एआई से जुड़ी 31,921 नौकरियां छंटनी या कर्मचारियों की कमी के रूप में प्रभावित हुईं। अर्थात, हर एक प्रभावित नौकरी के मुकाबले लगभग 2.6 नई एआई-संबंधित नौकरियां बनीं। मगर यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा कि एआई रोजगार की समस्या समाप्त कर रहा है। एआई नई नौकरियां जरूर बना रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिन लोगों की पुरानी नौकरियां जा रही हैं, वही लोग नई नौकरियों में प्रवेश कर पा रहे हों। यही भारत के सामने उभरती सबसे बड़ी रोजगार चुनौती है। नोमुरा के अनुसार, भारत में एआई अपनाने से एक 'दो-स्तरीय रोजगार बाजार' उभर रहा है। एक तरफ अनुभवी कर्मचारियों की मांग बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ फ्रेशर्स के लिए अवसर अपेक्षाकृत कम हो रहे हैं। भारतीय आईटी क्षेत्र की 651 कंपनियों पर किए गए आईसीआरआईईआर के सर्वेक्षण में 55 प्रतिशत कंपनियों ने बताया कि उनकी एंट्री-लेवल भर्ती में कमी आई है। इसके मुकाबले मिड-लेवल भर्ती में कमी बताने वाली कंपनियों का अनुपात 25 प्रतिशत और वरिष्ठ स्तर पर केवल 14 प्रतिशत था।

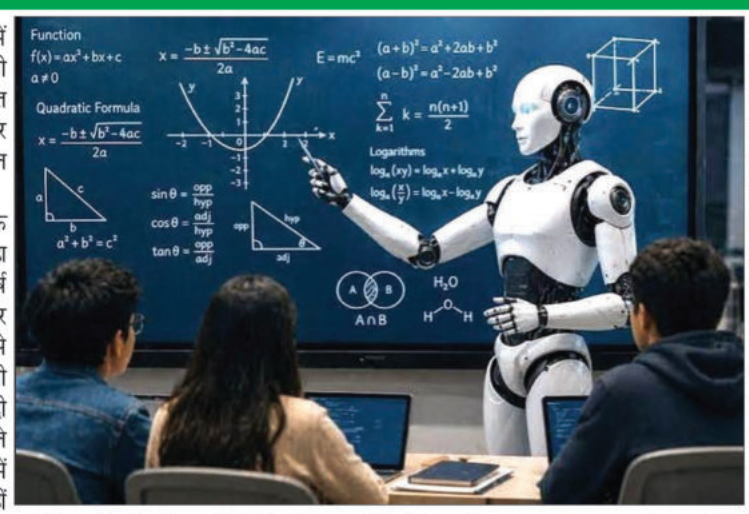

भारत की आर्थिक ताकत का एक बड़ा आधार हर वर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाली विशाल युवा आबादी है। यदि कंपनियां पहले की तरह बड़ी संख्या में फ्रेशर्स को नियुक्त नहीं करतीं तो समस्या केवल बेरोजगारी की नहीं होगी, बल्कि 'करिअर की पहली सीढ़ी' के कमजोर पड़ने की होगी। दरअसल, पारंपरिक कॉर्पोरेट व्यवस्था में एक युवा कर्मचारी सामान्य काम से शुरुआत करता था। वह डेटा तैयार करता था, रिपोर्ट बनाता था, बेसिक कोड लिखता था, गुणवत्ता जांच करता था, ग्राहक सेवा संभालता था और धीरे-धीरे अनुभव हासिल करके जिम्मेदार पदों तक पहुंचता था। एआई इन शुरुआती कार्यों का एक बड़ा हिस्सा तेजी से करने लगा है।

नोमुरा ने स्टाफिंग फर्म स्फेनो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय आईटी कंपनियों की नेट हायरिंग वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग छह लाख थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर करीब 1.40 लाख रह गई। कंपनियां बड़े पैमाने पर कैंपस भर्ती करने के बजाय कम, लेकिन कुशल कर्मियों को प्राथमिकता दे रही हैं।

यहां एआई को अकेला दोषी मानना भी उचित नहीं होगा। वैश्विक मांग, आईटी उद्योग का पुनर्गठन, लागत नियंत्रण और ऑटोमेशन जैसे कई कारक इस बदलाव के पीछे हैं। लेकिन एआई ने इस परिवर्तन की गति निश्चित रूप से बढ़ा दी है।

लेकिन अगर एआई नई नौकरियां बना रहा है तो वे नौकरियां किसके लिए हैं? एआई मॉडल विकसित करने वाले इंजीनियर, डेटा विशेषज्ञ, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, एआई ट्रेनर, डेटा एनोटेटर, भाषा विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एआई सिस्टम को व्यवसाय से जोड़ने वाले पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। नोमुरा के एशियाई अध्ययन में एआई से संबंधित नई नौकरियों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में केंद्रित था। इसका अर्थ यह है कि भारत के सामने अब केवल 'कितनी नौकरियां?' का सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है–'किस कौशल वाली कितनी नौकरियां?'

आने वाले वर्षों में एआई का असली मुकाबला उन कर्मचारियों के बीच होगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं और उन कर्मचारियों के बीच जो इसे केवल अपने रोजगार के लिए खतरा मानते हैं। एक अकाउंटेंट जो एआई आधारित विश्लेषण, ऑटोमेशन और डेटा टूल का उपयोग कर सकता है, उसकी उपयोगिता उस अकाउंटेंट से अधिक हो सकती है जो केवल पारंपरिक तरीके से काम करता है। इसी तरह एक पत्रकार जो शोध, डेटा विश्लेषण और प्रारंभिक ड्राफ्टिंग के लिए एआई का प्रभावी इस्तेमाल कर सकता है, वह तकनीक से प्रतिस्थापित होने के बजाय तकनीक की उत्पादकता बढ़ाने वाला पेशेवर बन सकता है। इसलिए भारत को 'एआई के साथ रोजगार' की रणनीति बनानी होगी।

डॉ. शशांक द्विवेदी

निस्संदेह, एआई युग में रोजगार का स्वरूप बदलने जा रहा है। संभव है कि भविष्य में एक कर्मचारी वही काम करे जो आज तीन लोग करते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे नए काम भी पैदा हों जिनकी आज कल्पना तक नहीं की गई है। आज देश के पास विशाल युवा आबादी, मजबूत आईटी उद्योग, अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं की क्षमता और दुनिया के लिए डिजिटल सेवाएं देने का अनुभव है। यदि इन ताकतों को एआई कौशल के साथ जोड़ा जाए तो भारत एआई-आधारित रोजगार का वैश्विक केंद्र बन सकता है।

प्रगतिशील सोच और जागरूकता से ही समाधान

भारत को प्रगतिशील, आधुनिक और विश्व के अग्रणी देशों में गिनते हुए हम नहीं थकते। देश की प्राचीन सांस्कृतिक गरिमा हमें गर्व का अनुभव कराती है, लेकिन मध्यकाल से लेकर आज तक चली आ रही अनेक जर्जर रूढ़ियां और परंपराएं हमें शर्मिंदा भी करती हैं। दास प्रथा भले ही समाप्त हो चुकी हो, पर छुआछूत, दहेज, बाल विवाह, शादी-ब्याह में फिजूलखर्ची और सामाजिक आडंबर जैसी कुरीतियां किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद हैं।

शादियों में बढ़-चढ़कर खर्च करना और दिखावे के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदर्शित करना एक प्रकार का कारोबार बन चुका है। डेस्टिनेशन वेडिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग भी चाहता है कि ऐसी शादियां भारत के सुंदर स्थलों पर हों, ताकि देश का धन देश में रहे, किंतु धनी वर्ग विदेशी स्थलों की ओर आकर्षित होता है। इससे अनावश्यक विदेशी खर्च बढ़ता है। जनजागरण के तमाम प्रयासों के बावजूद पुरानी रूढ़ियां नए रूपों में बार-बार सामने आ जाती हैं।

वर्षों से सामाजिक और कानूनी अभियानों के बावजूद देश में बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। यह माना जाता है कि आज लड़कियों को शिक्षा, प्रतियोगिताओं और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तथा वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। फिर भी कुछ राज्यों में बाल विवाह जारी हैं। कहीं न कहीं सामाजिक दबाव इसके लिए जिम्मेदार है।

महिला बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 27 अगस्त 2026 तक देश में बाल विवाह से जुड़े 3,863 मामले सामने आए। प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से 3,405 बाल विवाह रोके गए, जबकि पुलिस शिकायतों, बाल कल्याण समितियों की रिपोर्टों और विवाह निरस्तीकरण से जुड़े मामलों को मिलाकर 458 मामले दर्ज हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या समाप्त नहीं हुई है और सामाजिक जागरूकता के दावे पूरी तरह वास्तविकता से मेल नहीं खाते।

बाल विवाह रोकने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां 703 विवाह रोके गए। इसके बाद झारखंड में 534, हरियाणा में 531, त्रिपुरा में 353 और आंध्र प्रदेश में 326 बाल विवाह रोके गए। दूसरी ओर, बाल विवाह संबंधी आपराधिक मामलों में महाराष्ट्र में 154, राजस्थान में 152, पश्चिम बंगाल में 96 और छत्तीसगढ़ में 84 मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में देशभर की कुल शिकायतों का बड़ा हिस्सा केंद्रित

रहा। कुछ राज्यों में त्वरित पुलिस कार्रवाई से रोकथाम में उल्लेखनीय सफलता मिली, जिनमें हरियाणा और तमिलनाडु शामिल हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम तथा दादरा एवं नगर हवेली से बाल विवाह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इससे स्पष्ट है कि पूरा देश एक जैसी सामाजिक परिस्थितियों में नहीं जी रहा। फिर भी जिन बड़े राज्यों में आर्थिक और भौतिक विकास के दावे अधिक हैं, वहां भी बाल विवाह जैसी कुरीतियों का बने रहना हमारी प्रगति की असमान और विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करता है।

बाल विवाह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक दबाव, लैंगिक भेदभाव और कई अन्य विकृत मानसिकताओं से जुड़ी समस्या है। जिस देश में तेज आर्थिक विकास, मोबाइल और डिजिटल पहुंच तथा शिक्षा के विस्तार के दावे किए जाते हैं, वहां दहेज प्रथा का निर्बाध बने रहना भी गंभीर विरोधाभास है। दहेज को अक्सर 'उपहार' का नाम देकर सामाजिक स्वीकृति देने की कोशिश की जाती है, लेकिन विवाह और तलाक से जुड़े विवादों से स्पष्ट होता है कि आज भी लड़कियों के परिवारों पर कार, मकान और अन्य महंगी वस्तुएं देने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव डाला जाता है। विडंबना यह है कि विवाह संबंध तय करते समय लड़की के परिवार की आर्थिक क्षमता का आकलन इस दृष्टि से किया जाता है कि उपहारों के नाम पर कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। धनाढ्य वर्ग में भी बेमेल विवाह और आर्थिक हैसियत के आधार पर रिश्तों का निर्धारण दिखाई देता है।

सुरेश सेठ

अतः यह मान लेना आत्मप्रवंचना होगी कि भारत ने पुरानी सामाजिक कुरीतियों से पूरी तरह मुक्ति पा ली है। आधुनिकता केवल तकनीक, धन, उपभोग और ऊंची इमारतों से नहीं आती। वास्तविक आधुनिकता तभी संभव है, जब समाज महिलाओं को वस्तु या लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाली स्वतंत्र नागरिक और नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में स्वीकार करे। सवाल यही है कि भौतिकवाद की चकाचौंध के बीच ये घृणित रूढ़ियां आखिर कब टूटेंगी और भारतीय समाज अपने व्यवहार में सच्ची प्रगतिशीलता कब अपनाएगा?

सीसीटीवी कैमरे की जद में गंगा जलिया मंदिर

माही की गूंज, रतलाम।

अशोकनगर ग्रीन सिटी के पास स्थित गंगा जलिया मंदिर की प्रतिमा खंडित करने पर मचे बवाल और हिंदू संगठनों के तीव्र विरोध के बाद दूसरे दिन भी प्रशासन और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने मंदिर और इससे लगे पेड़ के साथ ही एक अन्य पेड़ पर दोपहर में ही सीसीटीवी कैमरे लगवाकर इसका एसेस अपने पास रख लिया। इससे यहां पर असामाजिक तत्वों या आने-जाने वालों की गतिविधियों की निगरानी रखी जा सके।चूंकि मंदिर और बावड़ी निजी जमीन पर होने से प्रशासन ने भूमि मालिक से दूरभाष पर चर्चा की। भूमि मालिक ने यहां स्वयं तार फेंसिंग करवाने की सहमति दी जबकि इस मंदिर से कुछ दूरी पर लोहे का गेट लगवाने की भी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ मंगलवार को यहां प्राण प्रतिष्ठा करवाने की पूरी तैयारी नहीं होने और मामले की गंभीरता को देखते हुए हिंदू संगठनों ने इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। अब पूरी तैयारी होने के बाद यहां प्राण प्रतिष्ठा करने की अलग से तारीख तय की जाएगी।

दोपहर में पहुंचे अफसर

सोमवार की दोपहर बाद घटनाक्रम सामने आने के बाद हिंदू संगठनों और बजरंग दल के तीव्र विरोध के बाद पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे थे। सोमवार को जैसे-तैसे मामला शांत कराया। मंगलवार को भी तहसीलदार कुलभूषण शर्मा, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, टीआई विक्रमसिंह चौहान के साथ हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। मुआयना करने के दौरान ही एएसपी राकेश पंद्रो भी पहुंचे और चारों तरफ की जानकारी जुटाई।

जबलपुर में रहते जमीन मालिक

प्रशासन ने यहां जानकारी जुटाई तो यह जमीन जीवनसिंह राजपूत की निकली। वे इस समय जबलपुर में रहते हैं और जमीन, मंदिर, बावड़ी की देखभाल के लिए नगरा के किसी व्यक्ति को यहां पर रखा हुआ है। प्रशासन की उनसे चर्चा के बाद केयर टेकर भी मौके पर पहुंचा। उसके अनुसार यह मंदिर व बावड़ी करीब डेढ़ सौ से दो सौ साल पुराना है। मुआयने के दौरान स्थानीय पार्षद सलीम बागवान, हिंदू संगठन के पदाधिकारी, पुलिस और प्रशासन के अफसर, राजस्व निरीक्षक और पटवारी सहित अन्य मौजूद रहे।

रामद्वारा की भी फेंसिंग होगी

अशोक नगर ग्रीन सिटी में प्राचीन रामद्वारा भी बना हुआ है। इसकी भी काफी जगह है किंतु कुछ जगह अतिक्रमण होने से यह मामला भी संवेदनशील हो गया है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी तगसीलदार शर्मा को वहां भी ले गए और पूरी स्थिति से अवगत कराया। तहसीलदार ने तार फेंसिंग करवाने की बात कही। जनसहयोग से यहां भी आगामी दिनों में तार फेसिंग करवा दी जाएगी। धर्मस्व विभाग से बजट स्वीकृत होने पर चारों तरफ बाउंड्रीवाल बनवाई जाएगी। इस पर मौजूद हिंदू संगठन पदाधिकारी सहमति हो गए।

सफाई कराई, मुरम डालेंगे

अशोकनगर ग्रीन सिटी से गंगा जलिया मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग पर कल तक भारी मात्रा में गंदगी और कचरा पड़ा हुआ था। विवाद के बाद इसे जेसीबी से हटवा दिया गया। अब इस मार्ग पर मुरम डलवाई जाएगी जिससे आवागमन सुगम हो सके।

तार फेसिंग करवाएंगे

गंगा जलिया मंदिर में प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया था। मंदिर और बावड़ी के यहां असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं। निजी जमीन पर बने मंदिर और बावड़ी के बारे में जमीन मालिक से चर्चा हो गई है। वे मंदिर के तारों तरफ तार फेसिंग करवाएंगे। एक सप्ताह में ये काम हो जाएगा। इसके बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हिंदू संगठन करवाएंगे। कुलभूषण शर्मा, तहसीलदार, रतलाम

संदिग्धों से कर रहे पूछताछ

मंदिर में मूर्ति को खंडित करने के मामले में पुलिस की जांच चल रही है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही असल आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। राकेश पंद्रो, एएसपी रतलाम

ट्रॉले से भिड़ी गलत साइड से आ रही कार

माही की गूंज, रतलाम।

बिलपांक थाना क्षेत्र के रत्तागिरी में महू-नीमच फोरलेन पर सोमवार-मंगलवार की रात करीब 2 बजे तेज गति से रांग साइड से आ रही कार सामने से आ रहे ट्रझले से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा घूमकर इंदौर की ओर हो गया।

हादसे में कार सवार दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे दो दोस्त घायल हो गए। चारों राऊ जिला इंदौर के निवासी हैं और रात करीब 12:30 बजे सोहनसिंह की कार से राजस्थान स्थित सांवरिया जी के दर्शन के लिए निकले थे। हादसे में 56 वर्षीय सोहनसिंह पुत्र बापूसिंह डाबी और 45 वर्षीय मुकेश पुत्र मानसिंह गहलोत की मौत हो गई। मुकेश कार चला रहा था और सोहनसिंह उसके बगल वाली सीट पर बैठे थे। पीछे बैठे 43 वर्षीय देवकरण पुत्र कन्हैयालाल मालवीय और 28 वर्षीय सावन पुत्र आसाराम मालवीय घायल हुए हैं। सोहनसिंह राऊ स्थित यूको बैंक में कैशियर थे। मुकेश लोडिंग वाहन चलाते थे। देवकरण कबानी का काम करते हैं, जबकि सावन ढोल वादक हैं। हादसे के बाद टोल की एंबुलेंस से घायलों को शासकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बाद में दोनों घायलों के स्वजन उन्हें अपने साथ इंदौर ले गए। एएसआई सतीश ठाकुर ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ट्राला जब्त कर थाने पर खड़ा करवा दिया गया है। रत्तागिरी निवासी प्रहलाद गणावा हादसे के बाद मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की। गणावा ने आरोप लगाया कि मृतक का शव ले जाने के लिए 108 एंबुलेंस करीब ढाई घंटे की देरी से आई। इससे रहवासियों में नाराजगी है।

पिता-पुत्र की एकसाथ उठी अर्थी

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले में शुजालपुर-आष्टा नेशनल हाईवे 752सी पर अरनिया कलां और तिलावद के बीच सोमवार दोपहर करीब 1 बजे सड़क हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के समीप दूध की पिकअप ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र का मौके पर ही निधन हो गया। वहीं, उनके साथ सवार एक अतिथि शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मंगलवार को मृतक के परिजनों ने पत्रिका से अपना दर्द बयां किया।

बीमार पिता को अस्पताल लेकर निकले अमर सिंह मालवीय, रास्ते में हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार तिलावद निवासी अमर सिंह मालवीय एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय तिलावद में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। उनके पिता जगन्नाथ सिंह मालवीय की अचानक तबीयत खराब होने पर अमर सिंह उन्हें उपचार के लिए बाइक से शुजालपुर लेकर जा रहे थे। उनके साथ विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ विजेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी गवांखेड़ा, जिला सीहोर भी बाइक पर सवार थे। बताया गया कि विजेन्द्र सिंह, अमर सिंह के पिता को संभालने के लिए उनके साथ बाइक पर बैठे थे। इसी दौरान अरनिया कलां की ओर से तिलावद की तरफ जा रही दूध की पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायल को शुजालपुर अस्पताल पहुंचाया गया।

वाहन छोड़कर भागा चालक

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। गमगीन माहौल में पिता-पुत्र का अंतिम संस्कार उन्हीं के गांव में किया गया।

क्षेत्र में शोक की लहर

अमर सिंह मालवीय मूल रूप से तिलावद निवासी थे और वर्तमान में शुजालपुर में निवास कर रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही तिलावद सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और फरार पिकअप चालक की तलाश की जा रही है।

मेरे पास पांच मिनट रुक जाते तो

मंगलवार को पत्रिका से बातचीत में अमर सिंह मालवीय के छोटे भाई दयाराम मालवीय ने बताया कि उनके बड़े भाई और उनके पिता का इलाके में सम्मान था। अमर सिंह सज्जन थे और छोटे बच्चों को भी %आप% कहकर संबोधित किया करते थे। दयाराम ने बताया कि अमर सिंह को अपने गांव से गहरा लगाव था। गांव से उनके परिवार का जुड़ाव इतना आत्मीय था कि उनके अंतिम संस्कार में समूचा गांव दोनों पिता-पुत्र को नम आंखों से अंतिम विदाई देने आया था।

दयाराम ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले उनकी बड़े भाई अमर से फोन पर बातचीत की थी। दयाराम ने बताया कि फोन पर अमर के आखिरी शब्द थे, ÷अमर, मुझे 50 किलो गेहूं चाहिए।÷अमर ने दयाराम से गेहूं लेने की बातचीत की और फोन रख दिया। छोटे भाई ने कहा कि अगर मेरे मोबाइल में बैलेंस होता या गेहूं लेने के लिए बड़े भैया पांच मिनट मेरे पास ही रुक जाते तो शायद हादसा न होता। दयाराम ने कहा कि अमर भैया और पिता ने परिवार का बोझ मुझ पर छोड़ दिया है। जब तक भाई थे, मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं था, लेकिन अब मैं अकेले कैसे संभालूंगा? दयाराम ने बताया कि बड़े भाई हमेशा कहते थे कि खुद टेंशन मत लो, दूसरे को टेंशन दो।

नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक

माही की गूंज, शाजापुर। शाजापुर में कुत्तों के आतंक ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। कुत्तों के काटने से घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचने वाले लोगों की संख्या चिंता का कारण बनी हुई है। स्थिति यह है कि एक सितंबर को जिला अस्पताल में कुत्तों के काटने के कारण 15 लोग उपचार कराने पहुंचे। नौ लोग इनमें शाजापुर शहर के निवासी हैं, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग आसपास के गांव क्षेत्र के निवासी हैं। इसके पहले 31 अगस्त को भी दो लोगों को शाजापुर में कुत्तों ने काटा था। दिनों दिन बढ़ रहे कुत्तों के आतंक ने लोगों को दहशत में डाल रखा है।

नगर पालिका ने नसंबदी अभियान चलाया

कुत्तों के आतंक से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी नगरीय निकाय और प्रशासन को दिशा निर्देश, गाइड लाइन जारी की थी। किंतु शहर में इसका भी प्रभावी ढंग से पालन नही हुआ है। कुत्तों पर नियंत्रण के लिए नगर पालिका ने नसंबदी अभियान चलाया, लाखों रुपये खर्च किए। बावजूद न तो कुत्तों के आतंक से मुक्ति मिली और न ही संख्या पर नियंत्रण हुआ। जिसके चलते विपक्ष द्वारा सिर्फ कागजों पर नसंबदी अभियान चलाने और लाखों रुपये का भ्रष्टाचार करने के आरोप भी नगर पालिका के जिम्मेदारों पर लगातार पूर्व में प्रदर्शन किया जा चुका है।

जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या के समाधान में सुस्त नजर आ रहे हैं

कुत्तों के हमलों की बढ़ती संख्या ने आमजन को परेशान कर रखा है किंतु जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या के समाधान में सुस्त नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुत्तों की संख्या में वृद्धि और उनके आक्रामक व्यवहार ने दहशत का माहौल निर्मित कर दिया है। इस स्थिति को देखते हुए, लोगों ने प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है।स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

लगातार कर रहे हैं प्रयास

कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और इससे राहत के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में नसंबदी अभियान भी चलाया जा चुका है। -प्रेम जैन, अध्यक्ष नपा

धोलावाड़ डेम 43 प्रतिशत भरा

माही की गिनिज, रतलाम।

सावन बीत गया और भादो शुरू हो गया। मालवा के रतलाम, मंदसौर और नीमच में कभी सावन में झड़ी लगती थी और भादों में गरज के साथ बारिश होती थी।, लेकिन मालवा की धरती अब भी उस बारिश का इंतजार कर रही है, जो खेतों के साथ जलाशयों और भूजल को भी भर सके। किसानों-आमजन को सितंबर माह में अच्छी बारिश की उम्मीद हैं। धोलावाड़ डेम 100 में से 43 प्रतिशत ही भरा हैं।

रतलाम, मंदसौर और नीमच में मानसून ने अब तक औसत के मुकाबले कम पानी दिया है। खेतों में मौजूद नमी ने फिलहाल खरीफ फसलों को संभाल रखा है, लेकिन आसमान की बेरुखी का असर अब जलस्रोतों में साफ दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ के बाद शुरू होने वाला रबी सीजन पानी के संकट में फंस सकता है।

16 इंच की कमी, धोलावाड़ भी 22.28 एमसीएम भरा

रतलाम जिले में अब तक 19.6 इंच औसत बारिश दर्ज हुई है, जबकि मानसून सत्र में सामान्य औसत करीब 36 इंच माना जाता है। यानी सामान्य आंकड़े तक पहुंचने के लिए करीब 16 इंच बारिश और चाहिए। आठ विकासखंडों में बाजना में सबसे कम 343 मिमी और रतलाम में सर्वाधिक 654 मिमी बारिश दर्ज हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में भी इस बार करीब 16 इंच बारिश कम है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खेतों में फिलहाल नमी होने से खरीफ फसल ठीक है, लेकिन जलस्तर की स्थिति चिंता बढ़ा रही है। धोलावाड़ जलाशय में 49.95 एमसीएम भराव की जरूरत के मुकाबले अभी सिर्फ 22.28 एमसीएम पानी है।

इनका कहना है

धोलावाड़ डेम 100 में से 43 प्रतिशत ही भरा हैं। साढ़े पांच मीटर अब भी खाली हैं। 22.28 एमसीएस पानी भरा है और वाटर सप्लाय के लिए 18 एमसीएम पानी की आवश्यकता होती है। बहुत स्थिति खराब हैं। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा अगर यही स्थिति रही तो। रतनसिंह मीना, एसडीओ

मंदसौर सितंबर से उम्मीद, खेतों में बढ़ रहा संकट

मंदसौर में अब तक 23.52 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य औसत से करीब 10 इंच कम है। गांधीसागर बांध की क्षमता 6607.42 एमसीएम है, वर्तमान भराव 4528.42 एमसीएम पहुंचा हैं। मौसम विभाग ने सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई है। पिछले वर्षों में सितंबर की बारिश ने जिले का कोटा पूरा करने के साथ जलस्रोतों को भी भरने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल खरीफ फसलों पर पीलामोजेक, अफलन और इल्लियों का प्रकोप बढ़ रहा है। खेतों में नमी घटने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में सितंबर की बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत बन सकती है।

नीमच : 240 मिमी कम, अब भी आसमान की ओर नजर

नीमच में अब तक 572.6 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 240 मिमी कम है। जिले में बारिश की कमी का असर साफ महसूस किया जा रहा है। सीताराम जाजू सागर बांध की क्षमता 6607.42 एमसीएम है, वर्तमान भराव 4420.71 एमसीएम पहुंचा हैं। खरीफ फसल फिलहाल सामान्य है, लेकिन जलस्रोतों की स्थिति चिंता पैदा कर रही है। सितंबर को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट राहत का संकेत नहीं है।

कालिया गैंग ने तीन राज्यों में चुराई 120 भैंसें

माही की गूंज, मंदसौर।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में 120 भैंसे चुरा चुके मंदसौर की कालिया गैंग के चार सदस्यों को चित्तौड़गढ़ जिले की निकुंभ थाना पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने गिरोह के मास्टर माइंड आरिफ कालिया को भी गिरफ्तार किया है। अभी चारों आरोपियों ने तीन राज्यों में 40 जगह से 120 भैंसों की चोरी करना कबूली है।

पुलिस की पूछताछ में मास्टरमाइंड आरिफ कालिया निवासी मुल्तानपुरा (मंदसौर) ने बताया कि गिरोह के सदस्य दोपहिया वाहन से मुल्तानपुरा से निकलते थे और पहले से तय रास्तों की रेकी करते थे। रात 9 से 10 बजे के बीच सुनसान बाड़ों के आस-पास पिकअप खड़ी कर उसमें भैंसों को चढ़ा देते थे। पिकअप में केवल चालक रहता था जो पहचान छुपाने के लिए मुंह ढंककर बिना नंबर की पिकअप चलाता था। बाकी आरोपित मोटरसाइकिल से ही आते-जामे थे। चुराई गई भैंसों को मंदसौर जिले के धुंधड़का पशु हाट में बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे।

हादसे के बाद भी पुलिस ने नहीं मानी हार

28 जुलाई को चित्तौड़ जिले के ग्राम गरदाना से हुई चोरी के बाद चित्तौड़ एसपी धर्मेंद्रसिंह यादव के निर्देश पर निकुंभ थाना अधिकारी प्रभुसिंह चुंडावत की टीम ने जांच शुरु की। 31 जुलाई की रात में मंदसौर से लौटते समय पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से कई जवान गंभीर घायल हो गए।

टीम ने मुखबिर और तकनीकी मदद से मालनखेड़ी के पास गिरोह के मास्टर माइंड 25 वर्षीय आरिफ कालिया, 25 वर्षीय सरफराज, 33 वर्षीय शहजाद, 25 वर्षीय आसिफ चारों निवासी मुल्तानपुरा थाना वायडी नगर मंदसौर को गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप और मोटरसाइकिल जब्त कर ली हैं। आरोपितों ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, गुजरात के अहमदाबाद, गांधी नगर तथा मप्र के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर सहित कई जिलों में भैंस चोरी कबूल की है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और चोरी गई भैंसों की बरामदगी में जुटी है।

चार बच्चों को लेकर कुएं में कूदने वाली महिला को चार बार अजीवन कारावास

माही की गूंज, मंदसौर।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गरोठ निरंजन कुमार पांचाल ने दो साल पहले चार बच्चों को कुएं में धकेलकर हत्या करने वाली महिला को चार बार के आजीवन कारावास से दंडित किया। साथ ही 2000-2000 रुपये का जुर्माना भी किया था।

आरोपी सुगनाबाई पत्नी रोड़सिंह बंजारा प्रतिदिन पति से होने वाले झगड़े से परेशान थी और इसके चलते ही चारों बच्चों को धकेलकर खुद भी कुएं में कूद गई थी पर ग्रामीणों ने सुगनाबाई को बाहर निकाल लिया और बच्चों को नहीं बचा पाए थे।

अभियोजन के अनुसार गरोठ तहसील के ग्राम पीपलखेड़ा में 14 जुलाई 2024 को सुबह 6ः15 बजे सुगनाबाई ने पति रोड़सिंह की प्रताड़ना से तंग आकर खेत पर बने कुएं में अपने चार बच्चों कार्तिक 2 वर्ष, बंटी 9 वर्ष, अनुष्का 7 वर्ष, मुस्कान 4 वर्ष को धकेलकर खुद भी कूद गई थी। इसी दौरान वहां पहुंचे ग्रामीणों ने सुगनाबाई को तो बचा लिए पर चारों बच्चों की मृत्यु हो गई थी।

गरोठ पुलिस ने सुगनाबाई व उसके पति रोड़सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1), 85, 55, 3 (5) के तहत प्रकरण दर्ज किया। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश निरंजन कुमार पांचाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित सुगनाबाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत प्रत्येक बच्चे की मृत्यु के लिए पृथक-पृथक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2000-2000 रुपये अर्थदंड भी किया।

सुबह भाई को फोन कर कहा था- हम मरने जा रहे हैं

14 जुलाई 2024 को ग्राम पीपलखेड़ी में सुबह लगभग 6 बजे सुबह सुगनाबाई ने भाई को फोन कर कहा था कि अब हम मरने जा रहे हैं। इसके बाद 40 वर्षीय सुगनाबाई पत्नीप रोड़सिंह बंजारा ने अपने चार बच्चों 9 वर्षीय बंटी, 7 वर्षीय अनुष्का, 4 वर्षीय मुस्कान और 2 वर्षीय कार्तिक को पहले कुएं में धकेलकर खुद ने भी छलांग लगा दी थी।

शादी के बाद से ही पति शराब पीकर मारपीट करता था

हादसे में चारों बच्चों की मौत हो गई। सुगनाबाई को ग्रामीणों ने बचा लिया। बाद में उसने गरोठ की तत्कालीन एएसपी हेमलता कुरील को बताया था कि लगभग 17 वर्ष पहले शादी हुई थी। शादी के बाद से ही रोड़सिंह बंजारा शराब पीकर मारपीट करता था और प्रताड़ित करता रहता था।

घर में कलह बना रहता था

बच्चों के साथ भी ठीक से नहीं रहता था। इसके चलते घर में कलह बना रहता था। बच्चों व पत्नी को छोड़कर घर से भाग जाता और जब भी आता मारपीट करता रहता था। 13 जुलाई 2024 की रात को भी बच्चों सहित पत्नी के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था।

रात में चारों बच्चों को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र चली गई थी

पति की पिटाई से बचकर सुगनाबाई रात में चारों बच्चों को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र चली गई थी। रात भर वहीं रही। 14 जुलाई 2024 की सुबह बच्चों के साथ खेत पर पहुंची और कुएं में छलांग लगा दी। तब सुगनाबाई ने बताया था पति आए दिन मारपीट करता था। रात में शराब पीकर पीटा। मुझे और बच्चों को बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मैं गिड़गिड़ाती रही। इसके बाद मैंने मरने की ठान ली।

किसानों का प्रदर्शन, भूमि अधिग्रहण के चार गुना मुआवजे की मांग

माही की गूंज, बड़वानी।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347-बी (देशगांव-जुलवानिया) के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित बड़ी संख्या में किसान बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कलेक्टर परिसर के मुख्य द्वार के पास धरना देकर नारेबाजी की। उन्होंने अधिग्रहित जमीन के बदले चार गुना मुआवजा देने की मांग की।

भारतीय किसान संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष मंशाराम पंचोले ने बताया कि प्रदर्शन में अगलगांव, निहाली, बाजड़, रुई, बोबलवाड़ी और कादवी गांवों के किसान शामिल हुए। किसानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए इन गांवों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, राजपुर द्वारा 5 दिसंबर 2025 को अंतिम पुरस्कार जारी किया गया था। किसानों का कहना है कि उन्हें जारी किए गए इस पुरस्कार में निर्धारित मुआवजे को लेकर आपत्ति है।

किसानों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के अधिग्रहण पर दो का गुणांक तथा 100 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। किसानों का दावा है कि इसके अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए।

किसानों के अनुसार अगलगांव, निहाली, बाजड़, रुई, बोबलवाड़ी और कादवी पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तथा इनमें से कोई भी गांव नगरपालिका, नगर निगम या नगर परिषद की सीमा में शामिल नहीं है।

भारतीय किसान संघ ने 26 मार्च 2026 को झाबुआ जिले में जारी भूमि अधिग्रहण के पुरस्कार का उदाहरण भी दिया। किसानों का कहना है कि वहां आंदोलन के बाद उनकी मांग स्वीकार की गई थी और प्रचलित कानून के अनुसार चार गुना मुआवजा दिया गया। इसी आधार पर बड़वानी के प्रभावित किसानों को भी मुआवजा देने की मांग की गई है।

किसानों ने यह आरोप भी लगाया कि सरकारी कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, लेकिन संबंधित प्रक्रिया में इसका पालन नहीं किया गया। किसानों ने

वर्तमान पुरस्कार निरस्त कर नया पुरस्कार जारी करने तथा मौजूदा गाइडलाइन के आधार पर चार गुना मुआवजा देने की मांग की।

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। किसानों ने कहा कि उचित मुआवजा मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

भाजपा नेता के भाई पर दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज

माही की गूंज, खंडवा।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता फाजिल पटेल के भाई यासीन पटेल के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। हरसूद थाना क्षेत्र की एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार महिला ने आरोप लगाया है कि 25 अगस्त 2026 को शाम के समय उसका पति घर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान यासीन पटेल उसके घर पहुंचा और बिना अनुमति अंदर प्रवेश कर उससे अशोभनीय हरकत की तथा दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला का कहना है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ झूमाझटकी की। शोर मचाने पर वह वहां से चला गया और जाते समय उसे तथा उसके पति को धमकी भी दी।

महिला ने पुलिस अधीक्षक अगम जैन को आवेदन देकर मामले में कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि घटना के बाद आरोपी की ओर से समझौते का दबाव बनाया गया। महिला ने बताया कि आरोपी ने उसके पति से दूरभाष पर संपर्क कर माफी भी मांगी थी, जिसकी ध्वनि रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है।

शिकायत के आधार पर हरसूद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 333 एवं 351 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक लीला बघेल को सौंपी गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। इसके तहत संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएंगे तथा दूरभाष विवरण, ध्वनि रिकॉर्डिंग और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गैस सिलेंडर के बदले दिए 200 रुपए के संदिग्ध नोट, पुलिस ने शुरू की जांच

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के अंजड़ नगर में गैस सिलेंडर के बदले 200-200 रुपए के संदिग्ध नोट दिए जाने का मामला सामने आया है। मंगलवार शाम कमलेश गैस एजेंसी के वितरण वाहन के कर्मचारी अमित वर्मा को एक युवक ने सिलेंडर के बदले 200 रुपए के पांच नोट दिए। नोटों की बनावट और रंग देखकर कर्मचारी को संदेह हुआ, जिसके बाद उसने अंजड़ पुलिस को सूचना दी।

कर्मचारी अमित वर्मा ने बताया कि वह नगर में गैस सिलेंडर वितरित करने के लिए निकले थे। इसी दौरान एक युवक सिलेंडर लेने पहुंचा और उसने भुगतान के लिए 200 रुपए के पांच नोट दिए। नोटों को देखने पर सभी नोट एक जैसे दिखाई दिए। इनमें से तीन नोटों के क्रमांक समान थे, जबकि दो नोटों के क्रमांक अलग बताए गए हैं।

कर्मचारी के अनुसार नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर भी सामान्य नोटों की तुलना में हल्की दिखाई दे रही थी। नोटों का रंग भी सामान्य नोटों से अलग था। संदेह होने पर कर्मचारी ने युवक द्वारा दिए गए नोटों की जानकारी पुलिस को दी।

मामले की सूचना मिलने के बाद अंजड़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने युवक द्वारा दिए गए पांचों नोट अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये नोट युवक के पास कहां से आए और इन्हें बाजार में चलाने के पीछे किसका हाथ है।

अंजड़ थाना प्रभारी आरआर चौहान ने बताया कि नोट देने वाले युवक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह

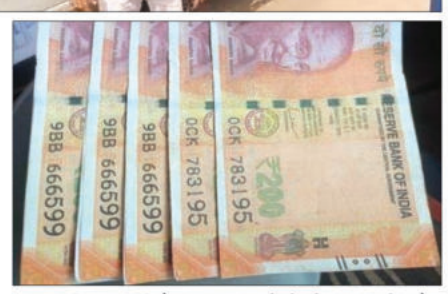

जानकारी जुटा रही है कि युवक को ये नोट कहां से और किस व्यक्ति के माध्यम से मिले। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में भी नकली नोट चलाने के आरोप में बोरलाय गांव की एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। अंजड़ पुलिस इस मामले की भी जानकारी जुटा रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं।

महिला को सिगरेट से 10 से अधिक जगह दागने का आरोप, पति पर हत्या का मामला दर्ज

माही की गूंज, खरगोन।

अंजुमननगर में 28 वर्षीय नीलोफर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति नईम फतेह खान के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई शव परीक्षण की रिपोर्ट और मृतका की 8 वर्षीय बेटी के बयान के आधार पर की गई है। मंगलवार को सामने आई शव परीक्षण रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोट और सिगरेट से दागने के कई निशान मिलने की जानकारी सामने आई। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार नीलोफर की करीब नौ वर्ष पहले नईम फतेह खान से शादी हुई थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी। 15 अगस्त को नीलोफर की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उसके पति ने परिजनों को बताया था कि उसने अम्लीय पदार्थ पी लिया है। इसके बाद उसे रामश्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए इंदौर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने शव को दफना दिया।

नीलोफर के मायके वालों ने उसकी मौत पर संदेह जताते हुए कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी। परिजनों ने पति पर मारपीट करने और सिगरेट से शरीर को दागकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन ने कार्यपालक दंडाधिकारी की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाया। 16 अगस्त को चिकित्सकों के दल ने शव का शव परीक्षण किया।

शव परीक्षण रिपोर्ट में नीलोफर के शरीर में विषैला पदार्थ पाए जाने की जानकारी सामने आई। इसके अलावा शरीर पर सिगरेट से दागने के 10 से अधिक निशान और चोट के निशान भी मिले। जांच के दौरान नीलोफर की 8 वर्षीय बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसकी मां के साथ मारपीट करते थे।

पुलिस ने बच्ची और मायके पक्ष के लोगों के बयान के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट को भी जांच में शामिल किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नईम फतेह खान के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि शव परीक्षण रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोट और जलाने के निशान मिले हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

आईएमआईएम ने पार्टी की इकलौती पार्षद के पति को किया निष्कासित

माही की गूंज, खंडवा।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के संगठन में मंगलवार देर रात बड़ा बदलाव सामने आया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने खंडवा शहर अध्यक्ष बिलाल खान उर्फ बिलाल पेंटर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उनके सभी संगठनात्मक पद और जिम्मेदारियां वापस लेने के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है।

प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी निष्कासन आदेश में कहा गया है कि आदेश प्रभावी होने के बाद बिलाल खान का पार्टी से कोई आधिकारिक संबंध नहीं रहेगा। वह पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न, पत्रशीर्ष, पदनाम अथवा किसी अन्य अधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही स्वयं को पार्टी का सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि बताकर किसी भी पार्टी गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

बिलाल पेंटर का निष्कासन इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि उनकी पत्नी शकीरा ने वर्ष 2022 में एआईएमआईएम के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीता था। उनकी जीत के साथ ही एआईएमआईएम ने मध्यप्रदेश में पहली बार निकाय चुनाव के जरिए अपना खाता खोला था।

यह कार्रवाई उस समय हुई है, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान सहित कई नेता मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। पार्टी की ओर से समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रदेशभर में रैलियां और आमसभाएं आयोजित की जा रही हैं। मंगलवार रात खंडवा में भी पार्टी की आमसभा आयोजित हुई थी। यह सभा बिलाल पेंटर के वार्ड में प्रस्तावित थी।

पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आमसभा में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी बिलाल पेंटर को दी गई थी। सभा में अपेक्षित संख्या में लोगों के नहीं पहुंचने और भीड़ कम रहने को लेकर पार्टी नेतृत्व की नाराजगी की चर्चा है। हालांकि, निष्कासन आदेश में भीड़ कम होने को कार्रवाई का आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है।

पार्टी से निष्कासन के बाद बिलाल पेंटर ने कहा कि उन्हें निष्कासन की कोई वजह नहीं बताई गई है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई से स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। बिलाल के अनुसार, उनके साथ करीब 30 कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

पंजाब मे चुनावी वादों के बीच भरोसा तलाशते मतदाता

पिछले सप्ताहांत से पंजाब में सिर्फ़ मौसम ही नहीं बदल रहा है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून, जो राज्य और देश के बाकी हिस्सों का पेट भरने वाली ज़मीन को सींचता है, हर साल की तरह समाप्ति पर है। इसके साथ ही हिंदू कैलेंडर का 'सावन' माह भी बीत गया। इसलिए, कल रात जब 'सावन' की आखिरी पूर्णिमा-यानी 'रक्खड़ पुन्या' या रक्षाबंधन-पर पूरा चांद निकला, तो उसकी चांदी सी चमक में आने वाले मौसम का राज़ भी छिपा था - कुछ ही महीनों बाद, सर्दियों में होने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब का ताज़ किसके सिर सजेगा?

ऐतिहासिक बाबा बकाला गुरुद्वारे में-जहां 1664 में नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर की पहचान उजागर हुई थी- 'रक्खड़ पुन्या' के मौके पर चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई। इस दिन पारंपरिक रूप से होने वाली रैलियों में सभी सियासी दलों ने ताकत दिखाई। पहली बार बीजेपी ने भी रैली की, जिससे संकेत मिला कि वह पंजाब में फिर वापसी करना चाहती है- चाहे अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से मिलकर या अकेले।

चुनाव में छह महीने बचे हैं और 'इंडिया टुडे' ग्रुप के 'मूड ऑफ़ द नेशन' पोल ने उल्टी गिनती को और तेज़ कर दिया है। इस पोल से पता चलता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए राष्ट्रीय वोट शेयर में 45.1 फीसदी के साथ काफी आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 39.1 प्रतिशत है-ज़ाहिर है, यहां प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती नहीं है। लेकिन बारीकी से राजनीति पर नज़र रखने वाले लोग देखेंगे कि एनडीए का वोट शेयर इस जनवरी में अनुमानित 47 प्रतिशत से 2 फीसदी कम हो गया है और यह एक साल पहले रहे 46.7 प्रतिशत से भी कम है।

तो अगले साल की शुरुआत में पंजाब के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों के लिए इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से, बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों से चली आ रही अपनी जीत की लय को बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है - तब से उसने कई राज्यों में शानदार जीत हासिल की है, चाहे वह हरियाणा हो, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार हो या पश्चिम बंगाल।

अब बीजेपी पंजाब जीतना चाहती है। उसे मालूम है कि वह उत्तर प्रदेश जीत सकती है, भले ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना हो; मणिपुर में भी जीत सकती है, भले ही वहां तीन साल से जातीय संघर्ष चल रहा है व अभी तक सुलझा नहीं; गोवा में भी, जहां वह लगातार तीन बार जीत चुकी। बंगाल जीतने के बाद, अब बीजेपी की

महत्वाकांक्षा देश के दूसरे छोर तक फैल गई। इसीलिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील करने बाबा बकाला गए और कहा, हमें वोट दें, हम आपकी समस्याएं हल करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई लोग पंजाब को कुछ समय से यही संदेश दे रहे हैं। हम आपका कर्ज़ माफ़ करेंगे, सीमा पार से ड्रोन के ज़रिए आने वाले नशों को रोकेंगे, खेती को बेहतर बनाएंगे, स्कूल ठीक करेंगे, सड़कें बनाएंगे और हरियाणा व राजस्थान के साथ पानी के बंटवारे का मुद्दा सुलझाएंगे। अनकहा संदेश? बीजेपी को वोट दें।

बेशक, पंजाब में कुछ खास बात है। यहां के लोग असाधारण दरियादिली दिखाते हैं- जैसे दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए गुरुद्वारों का खुलना और हाल के हफ़्तों में असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पंजाबियों का जाना- ऐसी दरियादिली देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं दिखती। इसकी सीमा एक मुश्किल पड़ोसी से लगती है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि बीजेपी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से क्यों नहीं खोल रही। बंगाल के उलट - आज़ादी के बाद उसका रिश्ता भी आजादी के बाद के 80 सालों में ज़्यादातर समय दिल्ली के साथ कांटे का रहा है, सिवाय पिछले कुछ महीनों के- पंजाब को दो बार बांटा गया- हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के रूप में - और आतंकवाद, उद्योगों के पलायन और हरित क्रांति के विपरीत प्रभाव ने इसकी अपनी छवि को और कमज़ोर किया है। पंजाबियों का एक शब्द है, जिसे वे कई स्थितियों के लिए काफी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह उनके वजूद की सबसे गहरी भावना से जुड़ा है - वह शब्द है 'धक्का', मतलब- 'मुझसे ज़बरदस्ती मत करो'। मसलन, 'मेरे तों धक्के नाल कम ना कराओ। यानी, मुझे मेरी मज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करने के लिए मजबूर न करें'।

यह एक ऐसा वाक्यांश है जिसे पंजाब को जीतने की चाह रखने वाले हर राजनीतिक दल को याद रखना चाहिए और अपने अंदरूनी दस्तावेज़ों में इसे एक नारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी का बिना मांगा सबक यह है कि पंजाब के 2.1 करोड़ वोटरों को - जो अब 1.9 करोड़ रह गए हैं, क्योंकि गहन मतदाता पुनरीक्षण की छलनी से गुज़रने के बाद लगभग 20 लाख वोटर छंट चुके हैं - धर्म (सिख, हिंदू), जाति (जाट, खत्री, रविदासिया, रामदासिया, वाल्मीकि आदि), डेरों (राधा स्वामी, सचखंड बल्लां, सच्चा सौदा आदि), धर्मगुरुओं (संत निरंजन दास, राम रहीम) के आधार पर बांटकर आप मान लें कि इनके वोटों को इकट्ठा कर सकेंगे। जिस राज्य को आप जीतना चाहते हैं, उसे बदनाम न करें, यह कहकर कि स्कूलों की हालत खराब हैं, कॉलेज का हाल और भी बुरा है, बुड्ढा दरिया एक गंदा नाला भर है, उद्योग बेपरवाह होकर दूषित पानी इसमें डाल रहे, गुंडागर्दी और नशे का बोलबाला है- भले ही इनमें से अधिकांश सच हों। अगर आप राज्य जीतना चाहते हैं, तो उसे बेहतर बनाने में मदद करें। स्पष्टतः राज्य को आपकी मदद की ज़रूरत है।

अब जबकि पंजाब में चुनाव से पहले के आखिरी छह महीने के दौर में दाखिल हो चुका है, और यह निरंतर साफ़ होता जा रहा है कि न तो भाजपा और न ही शिरोमणि अकाली दल अकेले दम जीत हासिल करने को ज़रूरी जोश पैदा कर पा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री को अहसास है कि इस अनोखे हालात पर नज़र रखने की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने गुजरात से अपने करीबी सहयोगी, नवसारी से चार बार के सांसद और गुजरात में भाजपा के पहले गैर-गुजराती प्रदेशाध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी है। दोनों पुराने सहयोगियों के बीच गठबंधन की संभावना इसलिए है कि उन्हें इसकी ज़रूरत है, न कि इसलिए कि वे ऐसा करना चाहते हैं।

ज्योति मल्होत्रा

यह मुकाबला लगातार काफ़ी अनोखा होता जा रहा है। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सब्सिडी वाली योजना से सीख ली है - जैसा कि भाजपा ने देश के दूसरे हिस्सों (हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली) में महिलाओं के बैंक खातों में पैसे डालकर कामयाबी हासिल की थी, वैसा ही आप इस राज्य में कर रही है। कांग्रेस, जो शायद अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, उसे तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि राहुल गांधी यह तय नहीं कर पा रहे कि उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा- अगले हफ़्ते राज्य का उनका दौरा पार्टी में चल रही गुटबाज़ी पर आखिरी मुहर लगा देगा। इस बीच, जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के संगठन 'वारिस पंजाब दे' और उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है।

मतदान से पहले के, अगले छह महीने बहुत अहम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब के लोग राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों का आकलन इस आधार पर नहीं करेंगे कि वे किस रंग की पगड़ी पहनते हैं - या पड़ोसी राज्यों से आने वाले नेता इसे कभी-कभार क्यों पहनते हैं - बल्कि इस आधार पर करेंगे कि रैलियों, भाषणों और नुक्कड़ सभाओं में वे जो कहते हैं, क्या सच में वही उनका मंतव्य भी है। जॉन एफ. कैनेडी की मशहूर उक्ति को कुछ हेरफेर से कहें तो - 'यह मत पूछिए कि पंजाब आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह कि आप अपने प्यारे राज्य के लिए क्या कर सकते हैं।'

पुलिस का सामना सांप से, डर के मारे टेबल पर चढ़े जवान

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले के नागदा थाने में रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिसकर्मियों का सामना एक जहरीले सांप से हो गया। अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस जवान इधर-उधर भागते नजर आए।

हालात इतने दिलचस्प रहे कि एक पुलिसकर्मी डर के मारे टेबल पर जा चढ़ा. खास बात ये रही कि सांप को पकड़कर जार में बंद किया गया, लेकिन वो वहां से भी निकल भागा और दोबारा थाने में दौड़ने लगा।

नागदा पुलिस थाने में सोमवार रात अचानक एक जहरीला सांप घुस आया। थाने में सांप दिखाई देते ही पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए पुलिसकर्मियों का पूरा ध्यान अपराधियों से हटकर इस बिन बुलाए मेहमान को पकड़ने पर लग गया।

सांप के डर से पुलिसकर्मी टेबल पर चढ़ा रहा

सांप के जहरीला होने की जानकारी सामने आते ही जवानों ने उससे दूरी बना ली। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी खुद को सुरक्षित रखने के लिए टेबल पर चढ़ गया और सांप के पकड़े जाने तक वहीं बैठा रहा। सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम के नितिन पांचाल को बुलाया गया। नितिन ने काफी मशक्कत के बाद सांप को काबू में किया और जार में बंद कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

जार से फिर निकल गया सांप

जार में बंद किया गया सांप अचानक बाहर निकल आया और थाने के अंदर ही तेजी से भागने लगा। सांप को दोबारा खुले में देखकर पुलिसकर्मियों में फिर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, रेस्क्यू एक्सपर्ट नितिन पांचाल ने बिना घबराए सांप को दोबारा पकड़ लिया। इस बार उसे सुरक्षित तरीके से काबू में करने के बाद थाने से बाहर ले जाया गया।

रेस्क्यू के बाद सांप की पहचान कॉमन करैत के रूप में हुई। बताया गया कि कॉमन करैत भारत में पाए जाने वाले बेहद जहरीले सांपों में शामिल है और इसकी लंबाई करीब चार से पांच फीट तक हो सकती है।

कुल मिलाकर, सोमवार रात नागदा थाने में कुछ देर के लिए ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिसकर्मी खुद एक जहरीले सांप से बचते नजर आए। रेस्क्यू के बाद जब सांप सुरक्षित थाने से बाहर निकला, तब जाकर पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली।

भाजापा मंडल अध्यक्ष की मांग पर मंत्री जी के संज्ञान पर चिकित्सक की नियुक्ति

माही की गूंज, आम्बुआ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आम्बुआ में चिकित्सकों की कमी के कारण आ रही परेशानी के मद्देनजर आम्बुआ भा.जा.पा मंडल अध्यक्ष भरत माहेश्वरी द्वारा मंत्री जी को पत्र द्वारा चिकित्सक की नियुक्ति बाबद अनुरोध किए जाने के फल स्वरूप एक अस्थाई चिकित्सक की व्यवस्था का समाचार प्राप्त हुआ है।

आम्बुआ स्वास्थ केन्द्र पर लंबे समय से चिकित्सकों की कमी बनी हुई है जिस कारण आम्बुआ सहित लगभग 37 ग्रामों से अधिक ग्रामों के बीमारों को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है या फिर निजी चिकित्सकों से इलाज कराना पड़ता है। विशेष कर शाम से रात तक तथा सुबह 11 बजे तक मरीज परेशान होते रहते हैं। अचानक हुए बीमार तथा दुर्घटना में घायलों को तत्काल इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण जिला मुख्यालय पर भेजना पड़ता है। वर्तमान में जो प्रमुख चिकित्सक है वे स्वयं अस्वस्थ होने के कारण सेवाएं देने में असमर्थ हैं। एक अन्य चिकित्सक दिन में सेवाएं दे रहे हैं, एक महिला चिकित्सक की भी स्थाई रूप से जरुरत है।

इस परेशानी को देखते हुए आम्बुआ भा.जा.पा मंडल अध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने एक पत्र अनुसूचित कल्याण मंत्री नागरसिंह चौहान को दे कर स्थिति से अवगत कराया। मंत्री चौहान द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर कर व्यवस्था करने का निर्देश दिया जिस पर जिला मुख्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट से डॉ. गणेश पवांर को आम्बुआ स्वास्थ केन्द्र पर तैनात किया गया है। वे भी प्रतिदिन आना जाना करेंगे ऐसी स्थिति में रात्रि कालीन परेशानी तो बरकरार ही रहेगी। चिकित्सक के आवास जीर्ण शीर्ण होने से उसमें रहना मुश्किल है। इस लिए आवास भवन की व्यवस्था भी जरूरी है ताकि चिकित्सक रह सकें।

व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अधिकारियों को छात्रावास आवंटित

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने जिले में संचालित जनजातीय छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कार्ययोजना बनाई गई है। छात्रावासों की व्यवस्थाओं की नियमित एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला अधिकारियों को एक-एक छात्रावास आवंटित कर गोद दिया गया है।

कलेक्टर ने बताया कि, छात्रावास गोद लेने वाले अधिकारी संबंधित छात्रावास के नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे। नोडल अधिकारी नियमित रूप से छात्रावासों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उनके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने कहा कि छात्रावास केवल विद्यार्थियों के रहने का स्थान नहीं, बल्कि उनके शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, अनुशासन एवं सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देना जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण दायित्व है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं की नियमित समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार उनमें सुधार किया जाए। विद्यार्थियों के लिए ऐसा सकारात्मक एवं प्रेरणादायी वातावरण तैयार किया जाए, जहां वे बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रावासों की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोडल अधिकारी नियमित निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं पर सतत निगरानी रखें तथा किसी भी प्रकार की कमी या समस्या सामने आने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, सुविधायुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक आयोजित

माही की गूंज, धार।

मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा एवं सदस्य सोमिन निमामा ने 31 अगस्त को धार जिले के प्रवास के दौरान महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग सहित संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समन्वय बैठक की।

बैठक में बाल अधिकारों के संरक्षण, बच्चों से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिले में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। आयोग की अध्यक्ष ने अधिकारियों को बाल अधिकारों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्राम धानी स्थित प्रोजेक्ट विद्यालय द्वारा संचालित बालिका छात्रावास का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए। साथ ही छात्राओं की सुरक्षा, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

बैठक में पुलिस विभाग द्वारा जिले में चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक करने तथा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी आयोग की अध्यक्ष को दी गई।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, सहायक संचालक शिक्षा, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बलराम कृषि महोत्सव

माही की गूंज, आलीराजपुर।

ग्राम पंचायत कनपुर में बलराम कृषि महोत्सव एवं भगवान बलराम जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण एवं टिकाऊ खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

उप संचालक कृषि सहित कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत एवं नीमास्त्र जैसे प्राकृतिक कृषि इनपुट के उपयोग की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भगवान बलराम के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मिट्टी, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ कृषि को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान बडी संख्या में ग्रामीणजन एवं कृषक उपस्थित थे। उक्त जानकारी कृषि विभाग ने दी।

विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

सचिव जि.वि.से.प्रा. जय पाटीदार एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शक्ति रावत द्वारा उप जेल जोबट का निरीक्षण किया गया तथा जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में निरूद्ध बंदियो की समस्याएं जानी तथा जेल में स्वच्छता, सफाई, बंदियों के भोजन एवं स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधा आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के पश्चात् उप जेल जोबट में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीयो द्वारा बन्दियों को अपील के अधिकार, प्री-मेच्योर रिलीज एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति-जनजाति का सदस्य हो या बालक हो या महिला हो या जेलबंदी हो या औद्यौगिक कर्मकार हो या जिसकी समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रूपये दो लाख से कम हो, ऐसा व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी होता है, योजना अंतर्गत न्याय शुल्क एवं अधिवक्ता शुल्क व प्रतिलिपि शुल्क की व्यवस्था प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा लाभांवित व्यक्ति को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता।

साथ ही,12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में तहसील न्यायालय जोबट में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष हिमांशु शर्मा तहसील विधिक सेवा समिति जोबट की अध्यक्षता में अधिवक्ता संघ जोबट के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रैफर एवं निराकरण करवाकर पक्षकारों को लाभांवित किये जाने हेतु अधिवक्ता संघ से आवश्यक सहयोग की अपील की गई, जिस पर अधिवक्ताओं द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में सहभागिता हेतु प्रयास किया जाना व्यक्त किया।

ग्राम मालवई में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे ''पंच-ज'' अभियान (जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर) के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन हेतु पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान सचिव जि.वि.से.प्रा., जेएमएफसी ,जिला विधिक सहायता अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, चीफ एलएडीसीएस,सहायक जेल अधीक्षक उप जेल जोबट, जेल कर्मचारीगण तथा जेलबंदी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल ,अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिला न्यायालय में किया गया मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

माही की गूंज, धार।

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला अभिभाषक संघ धार के सभाकक्ष में न्यायालय के सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अभिभाषकगण एवं उनके परिवार हेतु एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य न्यायालय परिसर में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों और न्यायालयीन कर्मचारियों व उनके परिजनों तथा अभिभाषकगण को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हितेष ठाकुर, विशेष न्यायाधीश श्रीमती मेरी माग्रेरट फ्रांसिस डेविड, सहित जिला मुख्यालय में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रदीप सोनी, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव संतोष जाट, जिला चिकित्सालय धार से डॉ. मनीष मोदी, डॉ. प्रतिक पटेल, डॉ. सागर गुप्ता, डॉ. हर्ष नारगा, डॉ. मोहित जाधव, डॉ. डिम्पी सिलावट, डॉ. शैफाली हाडिया, डॉ. अदिती बिटोरिया, डॉ. अदिती रावत, डॉ. वैशाली, डॉ. गौरव गुप्ता, डॉ. अंकित चौरसिया एवं उनकी टीम जिला न्यायालय के अधिकारी कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहें। उक्त मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में जिला चिकित्सालय के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दीं। शिविर में उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञों ने मेडिसिन विशेषज्ञ, स्त्री रोग, अस्थि रोग, नेत्र रोग, दंत रोग, चर्म रोग एवं सामान्य चिकित्सा से संबंधित लगभग 350 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किए। आयोजन के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश / सचिव प्रदीप सोनी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर टीम एवं पैरामेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त किया।

नरभक्षी अघोरी पर एफआईआर

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले के चक्रतीर्थ स्थित एक शमशान घाट से जलती चिता में से शव का मांस खाने वाली अघोरी तांत्रिक काली उर्फ नंद गिरी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि किन्नर अखाड़े से जुड़ी अघोरी तांत्रिक काली उर्फ नंद गिरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह जलती चिता से तलवार के जरिए इंसानी मांस निकालकर खाते हुए नजर आ रही है।

वीडियो में तांत्रिक को 'यह बहुत टेस्टी है' और 'मैं तुम्हारे जीवन से खेलूंगी' जैसी अमानवीय बातें कहते हुए सुना जा सकता है। इस वीभत्स वीडियो के वायरल होने के बाद आम जनता के साथ-साथ संत समाज में भी भारी आक्रोश था। महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे वैदिक परंपरा और अघोर मर्यादा के खिलाफ बताया था और अघोरी तांत्रिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

वीडियो वायरल होने और संत समाज (विशेषकर अघोर व जूना अखाड़े) के भारी आक्रोश के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। शव के साथ छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 301 व अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है

एफआईआर के बाद बनाया एक और वीडियो

पुलिस ने आरोपी अघोरी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसका एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वह पुलिस और विरोध करने वालों को चुनौती देती व धमकी देती नजर आ रही है। संतों और स्थानीय नागरिकों ने इस कृत्य को सनातन धर्म और अघोर परंपरा की आड़ में किया गया एक घिनौना, अमानवीय व पब्लिसिटी बटोरने वाला स्टंट बताया है। पुलिस फिलहाल मामले की विस्तृत जांच और वीडियो की फोरेंसिक पुष्टि कर रही है।

क्या है पूरा मामला

वायरल वीडियो में तांत्रिक काली उर्फ नंद गिरी यह कहते हुए नजर आती है कि वह चिता से मांस खाएगी। इसके बाद वह हाथ में तलवार लेकर जलती चिता के पास जाती और उसमें से मांस निकालकर खाने का दावा करती है। वीडियो सामने आने के बाद उज्जैन के साधु-संतों और अघोर परंपरा से जुड़े लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वीडियो में वह यह कहती हुई सुनाई देती है कि %हम आज इंसान का मांस खाएंगे। इसके बाद वह तलवार की मदद से चिता में से कुछ निकालती है और उसे खाने का दावा करती है।

टूटते बेरिकेड्स, प्रशासन पर घटते भरोसे की निशानी

माही की गूंज, झाबुआ।
धर्मेंद्र पंचाल

झाबुआ में कई राजनीतिक दलों, विभिन्न संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और दबाव समूहों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपना रोजमर्रा की प्रक्रिया है। कलेक्टर ने ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम को अधिकृत कर रखा है। इसलिए अधिकांश ज्ञापन एसडीएम को ही दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब कलेक्टर स्वयं किसी अवसर पर ज्ञापन लेने पहुंचते हैं, तो संगठनों में अपना ज्ञापन सीधे कलेक्टर को सौंपने की होड़ दिखाई देती है। यह स्थिति एक अहम सवाल खड़ा करती है। क्या लोगों को लगता है कि, कलेक्टर तक सीधे पहुंचने से उनकी समस्या पर कार्रवाई अधिक तेजी से होगी...?

यदि एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापनों पर भी प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई हो तथा उसकी जानकारी आवेदक को मिलती रहे, तो कलेक्टर तक पहुंचने की यह बैचेनी स्वाभाविक रूप से कम हो सकती है। प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारों का विकेंद्रीकरण तभी प्रभावी माना जाएगा, जब नागरिक को हर स्तर पर समान भरोसा मिले।

हर शिकायत का तत्काल समाधान संभव नहीं। लेकिन कार्रवाई की शुरुआत, जिम्मेदार विभाग, समयसीमा और प्रगति की जानकारी देना संभव है। जनता को सबसे पहले यह भरोसा चाहिए कि, उसका ज्ञापन केवल स्वीकार नहीं हुआ, बल्कि प्रक्रिया में आगे भी बढ़ा है।

इसे तकनीक से और प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रत्येक ज्ञापन स्वीकार होते ही उसका विशिष्ट पंजीकरण क्रमांक या क्यूआर कोड जारी हो। मोबाइल पर सूचना मिले और आवेदक उसी

के माध्यम से देख सके कि, ज्ञापन किस विभाग को भेजा गया, किस अधिकारी के पास है और उस पर क्या कार्रवाई हुई।

इससे सुविधा के साथ जवाबदेही भी बढ़ेगी। प्रशासन लंबित मामलों की निगरानी कर सकेगा और आवेदक को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

क्योंकि जब ज्ञापन पर कार्रवाई का भरोसा कमजोर होता है तो ज्ञापन, प्रदर्शन में और प्रदर्शन, टकराव में बदल सकता है। ऐसे में टूटते बैरिकेड केवल कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं रहते, वे प्रशासन और जनता के बीच घटते भरोसे का संकेत भी बन जाते हैं।

आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन बैरिकेड तोड़ना या कानून-व्यवस्था बिगाड़ना उचित नहीं। प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने के साथ यह भी देखना होगा कि, टकराव की नौबत आने से पहले संवाद और कार्रवाई की कौन-सी कड़ी कमजोर हुई।

झाबुआ में जरूरत बैरिकेड मजबूत करने से अधिक ज्ञापन से समाधान तक की व्यवस्था मजबूत करने की है। यदि प्रत्येक ज्ञापन की डिजिटल निगरानी हो और आवेदक को उसकी स्थिति मोबाइल पर दिखाई देती रहे, तो यह व्यवस्था प्रशासन और जनता के बीच भरोसे की नई कड़ी बन सकती है।

यदि आदिवासी बाहुल झाबुआ जैसे जिले में यह नवाचार सफल होता है, तो इसे केवल स्थानीय प्रयोग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी एक प्रभावी और अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।

जनता को हर बार कलेक्टर का हाथ नहीं चाहिए, उसे यह भरोसा चाहिए कि, जिस अधिकारी के हाथ में उसका ज्ञापन गया है, वह उस पर कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे मजबूत सुरक्षा-व्यवस्था बैरिकेड नहीं, जनता का प्रशासन पर भरोसा होता है।

माता-पिता की गलती, परिवार का तिरस्कार अब भांजगडी प्रथा में भी अड़ंगा

मामला : दो पंचायत के पूर्व सरपंच के परपोते व पोती के भाग कर शादी करने के बाद उपजा विवाद

कदवाली के ग्रामीणों ने मामले की माही की गूंज को दी जानकारी।

सुनील का मामा हुरसिंग कर रहा सुरक्षा की मांग।

माही की गूंज, खवासा।
सुनिल सोलंकी

27-28 वर्ष पूर्व माता-पिता ने जो गलती की उसका हर्जाना अब तक उनके पुत्र माता-पिता की मौत के बाद परिवार के तिरस्कार के साथ भुगतना पड़ रहा है। वहीं परिवार का तिरस्कार भांजगडी प्रथा में भी अड़ंगा बन रहा है जो पड़ोसी दो ग्राम पंचायत के ग्रामों में बड़े विवाद का कारण बन गया है। मामला यह है कि, माही की गूंज ने अपने 3 अप्रैल 2025 के अंक में ''समाज में जीने के लिए परिवार का अपनाना आवश्यक'' ''माता-पिता की गलती को उनके मरने के बाद भी भुगत रहे हैं दो युवक, परिवार कर रहा तिरस्कार'' शीर्षक के साथ प्रकाशित समाचार में खुलासा किया था कि, शादी-शुदा व्यक्ति अपने ही परिवार की महिला को ले गया और दोनों पति-पत्नी की मौत के बाद जैविक दोनों पुत्रों का तिरस्कार परिवार ने कर दिया। जिससे हक के लिए जैविक पुत्रों ने अपने हक एवं परिवार द्वारा उन्हें अपनाए जाने हेतु न्याय की उम्मीद के साथ 3 अप्रैल 2025 के पूर्व एसपी कार्यालय तक अपनी रिपोर्ट पेश कर न्याय की उम्मीद की थी। लेकिन प्रशासन ने मामले को हल्के में लिया और जैविक पुत्रों के हक में कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं की गई। उक्त खुलासा माही की गूंज ने किया था जो आज फिर एक विवाद का कारण बना हुआ है।

मामला यह कि, मादलदा ग्राम पंचायत के लंबे समय तक सरपंच रहे व जिले में अपना नाम कायम करने वाले रादु बॉ भूरिया सरपंच व उसका भाई फूलजी दो भाई ग्राम कदवाली के थे। तात्कालिक सरपंच रादु भूरिया का पोता हवसिंग भूरिया करीब 27-28 वर्ष पूर्व अपने ही छोटे भाई फूलजी की लड़की कुंवरी बाई यानी अपनी बुआ को भगा कर ले गया।

बता दे कि, हवसिंग की शादी पारिवारिक रीति रिवाज से राज. की कांताबाई से हो चुकी थी तथा एक पुत्री के जन्म के बाद हवसिंग अपनी ही बूआ को लेकर भाग गया और वैवाहिक जीवन यापन किया तथा दो पुत्र सुनील एवं अनिल का जन्म कुवरी बाई से हुआ। करीब 10 साल बाद पोते हवसिंग व कुंवरी बाई को परिवार में शामिल किया जिसके बाद हवसिंग की पूर्व पत्नी कांताबाई ने भी हवसिंग के एक पुत्र को जन्म दिया। जिसके बाद करिब 14-15 वर्ष पुर्व किसी बीमारी के चलते पहले पिता हवसिंग की मौत हो गई। जिसके दो साल बाद कुंवरी बाई की भी मौत हो गई। हवसिंग की मौत के बाद पुनः परिवार ने कुंवरीबाई का तिरस्कार उसके पुत्रों के साथ कर दिया और दोनों पुत्रों को इंदौर के अनाथ आश्रम में एक के बाद एक को छोड़ दिया। जिसके बाद सुनील व अनिल बालिग होने के बाद अपना कार्य व जीवन यापन इंदौर में रहकर कर रहे हैं। वहीं परिवार के तिरस्कार के साथ अपनी मां कुंवरीबाई के भाई मामा हुरसिंह भूरिया के यहां आना-जाना रहा।

इसी कड़ी में कुंवरीबाई से जन्मे बड़े पुत्र सुनील अपने कदवाली गांव के समीप ग्राम पंचायत देवगढ़ के ग्राम भमरिया के पूर्व सरपंच धीरजी सिंगाड़ की पोती व हरजी सिंगाड़ की 19 वर्षीय बालिग पुत्री कविता के साथ पिछ्ली 25 मई को भाग गए। जिसके बाद इंदौर नगर निगम में अपना विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण करवा कर 29 मई 2026 का प्रमाणित उक्त विवाह प्रमाण पत्र के साथ हाई स्कूल पास की मार्कशीट व अपना आधार कार्ड जिसमें उनके बालिग होने के प्रमाण है के साथ प्रमाणित दस्तावेज पुलिस चौकी तक पहुंचा दिए गए।

ऐसे में पुलिस के पास उक्त मामले में कार्रवाई जैसा कोई कारण नहीं है क्योंकि दोनों बच्चे बालिक है। लेकिन वही लड़की के पिता हरजी एवं दादा धीरजी, सुनील के मामा हुरसिंह भूरिया पर मामले को भीली भांजगडी प्रथा के साथ लेनदेन कर खुटारा करने या लड़की को वापस लाने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं हुरसिंह ने चौकी से लेकर एसपी तक आवेदन देकर अपनी व परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

इसी कड़ी में माही की गूंज प्रतिनिधि को भी मादलदा की ग्राम पंचायत परिसर में पंचों को इकठ्ठा कर बुलाया और वस्तु स्थिति ग्राम वासियों के साथ हूरसिंह भूरिया ने बताई।

हूरसिंह का कहना था कि, भमरिया लड़की का परिवार हुरसिंग पर खुटारे को लेकर दबाव बना रहा है जो गलत है। हूरसिंह तो मां के नाते मामा लगता है जबकि रादु बॉ के पुत्र सकरिया दादा होकर उनका परिवार है और कानूनी हक से जो भी जवाबदारी होती है वह परिवार की होती है। इसलिए रादु जी के पुत्र परिवार ही मामले का निपटारा करें।

वहीं हूरसिंह ने बताया कि, वे कदवाली के कोतवाल है और खवासा तहसील कार्यालय पर उन्हें कार्य हेतु आना-जाना रहता है। वहीं उनके दो पुत्र है जो एक कॉलेज व एक खवासा स्कूल में अध्यनरत है।

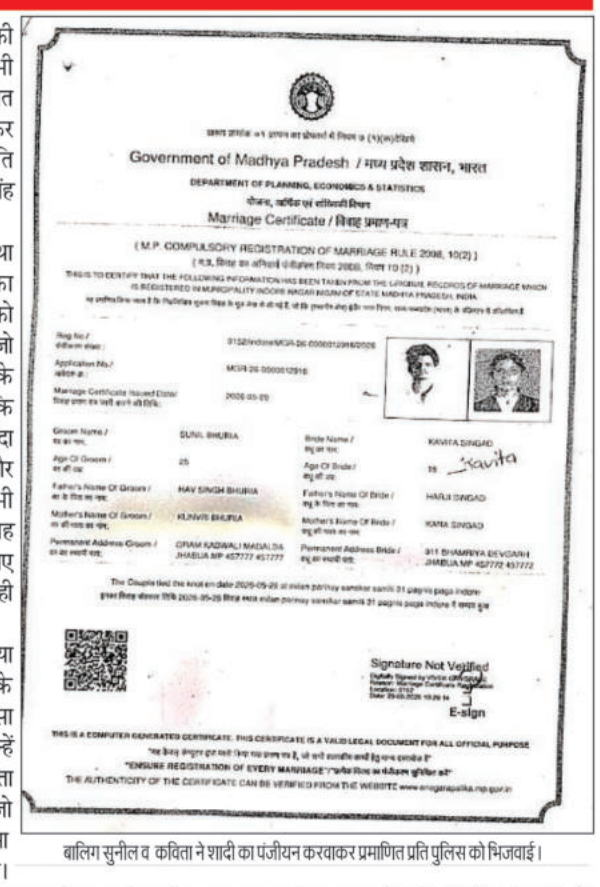

Government of Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश शासन, भारत

DEPARTMENT OF PLANNING, ECONOMICS & STATISTICS

Marriage Certificate / विवाह प्रमाण-पत्र

Signature Not Verified

E-sign

THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE. THIS CERTIFICATE IS A VALID LEGAL DOCUMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSE

"ENSURE REGISTRATION OF EVERY MARRIAGE"

THE AUTHENTICITY OF THE CERTIFICATE CAN BE VERIFIED FROM THE WEBSITE

बालिग सुनील व कविता ने शादी का पंजीयन करवाकर प्रमाणित प्रति पुलिस को भिजवाई।

लेकिन लड़के-लड़की के भाग जाने व शादी करने के बाद से ही लड़की का सिंगाड परिवार मुझ मामा पर दबाव बना रहे हैं व धमका रहे हैं जिसके चलते हमारा घर व गांव से खवासा तक भी आना-जाना दुश्वार हो गया है। हूरसिंह ने मांग की है कि, रादु जी का पूरा परिवार मामले को भीली भांजगढ़ी में निपटाए और पुलिस से मांग की है कि, वह मामले में हस्तक्षेप कर भमरिया के सिंगाड़ परिवार से सुरक्षा प्रदान करें ताकि मेरा कार्य व बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

केंद्र सरकार तक तमाचा: प्रतिबंधित कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस का हो रहा उत्पादन और बिक रहा बाजार में

माही की गूंज, खवासा।

देश में किसी भी प्रतिबंधित सामग्री का उत्पादन होना और उसका खुले आम विक्रय होना ही यह दर्शाता है कि, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम नश्तोनाबूंद हो गया है। जिसके कारण ही प्रतिबंधित सामग्री का महज उत्पादन भी हो रहा है और उसका विक्रय भी धड़ल्ले से हो रहा है। अगर ऐसा मामला कहीं भी प्रतिबंधित सामग्री का उत्पादन व विक्रय का सामने आता है तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक यह बड़ा तमाचा है।

पश्चिम क्षेत्र में बसे आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले के ग्राम खवासा में मंगलवार को शिकायतों के बाद कृषि विभाग की हुई कार्रवाई में सामने आया कि, प्रतिबंधित कीटनाशक का विक्रय धड़ल्ले से हो रहा है।

कब और क्यों हुआ मोनोक्रोटोफॉस प्रतिबंधित

भारत सरकार ने देश में अत्यंधिक विषैल कीटनाशक को बंद करने का निर्णय सन 2013 में लिया था तथा अत्यधिक विषैले कीटनाशक का भारत के अलावा पूर्व में अमेरिका के साथ अन्य देशों में भी प्रतिबंधित किया गया है।

भारत सरकार ने 8 जुलाई 2013 को विशेषयज्ञों की एक समिति बनाई जिसमें करीब 27 कीटनाशक दवाई जो की अत्यधिक विषैली है पर जांच करवाई गई व 2013 से अक्टूबर 2023 के बीच विशेषयज्ञ की टीम द्वारा प्रस्तुत सारे तथ्यों के आधार पर 29 सितंबर2023 को केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र क्रमांक सी.जी.डी.एस. अ./ई. 06102023-249185 दिनांक 23 सितंबर 2023 को जारी किया। जिसमें मोनोक्रोटोफॉस के साथ अन्य अत्यधिक विषैले कीटनाशक को प्रतिबंधित कर 8 अक्टूबर 2023 से उत्पादन व विक्रय पर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।

आदेश में अत्यधिक विषैले कीटनाशक जिन-जिन को बंद किया गया उन बचे हुए स्टॉक को 1 वर्ष की अवधि यानी अक्टूबर 2024 के पूर्व बेचने के आदेश भारत सरकार के थे। वही अक्टूबर 2024 से प्रतिबंधित कीटनाशक निर्माण से जुड़े सभी पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए थे। लेकिन खवासा में कृषि विभाग की कार्रवाई में सामने आया कि, प्रतिबंधित मोनोक्रोटोफॉस जिसका पूर्णतः उत्पादन ही 2023 में प्रतिबंधित कर दिया था और बचा स्टॉक अक्टूबर 2024 के पूर्व बेचना था या उसके बाद नष्ट किया जाना था। वहीं मोनोक्रोटोफॉस, कोर्टनेक्स एग्रो साइंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने प्रतिबंध के बाद 20 मार्च 2026 को उत्पादन किया जिसकी वैधता 21 मार्च 2028 के साथ 1265 रुपए के 1 लीटर की बोतल पर निर्धारित की हुई प्रतिबंधित मोनोफॉस की बोतल महाराष्ट्र से चलकर झाबुआ जिले के खवासा, राजस्थान सीमा तक पहुंची और मंगलवार को कृषि विभाग की कार्रवाई के दौरान बस स्टैंड पर एक किसान के हाथ में 1 लीटर वाली करीब दो बोतल प्रतिबंधित मोनोफॉस की बोतल जप्त की व पंचनामा बनाया। तो किसान ने जिस दुकान से यह प्रतिबंध 1265 एमआरपी वाली करीब 750 रुपए लीटर में क्रय करके लाया वह बताया।

प्रतिबंधित मोनोक्रोटोफॉस का उत्पादन होकर बिक रहा बाजार में।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

उक्त राजपत्र के आदेश के साथ अत्यधिक विषैली कीटनाशक प्रतिबंधित किया गया था जिसमें एक मोनोक्रोटोफॉस भी है।

कृषि विभाग की एसडीओ डामर मैडम के साथ अधीनस्थ अधिकारी की आने की जानकारी प्रतिबंधित उक्त कीटनाशक बेचने वाले व्यापारी को जैसे ही मिली प्रतिबंधित कीटनाशक की बोतल तत्काल दुकान व गोदाम से हटा दी गई बताया जा रहा है।

वहीं जब कृषि विभाग के अधिकारी बजरंगबली मंदिर के पास लोहार मोहल्ले में किसान द्वारा बताए गए कीटनाशक विक्रेता के यहां छापा मार कार्रवाई किए जाने पर कोई भी प्रतिबंध बोतल दुकान व गोदाम से नहीं मिली। लेकिन बताने वाले बता रहे हैं कि, कृषि विभाग की कार्रवाई के साथ पंचनामा बनाकर व्यापारी से किसान को खरीदी हुई प्रतिबंधित कीटनाशक का पेमेंट दिलवाया। तथा अन्य कीटनाशक विक्रेताओं के यहां पर भी कृषि विभाग की उक्त टीम ने अपनी जांच की लेकिन कृषि विभाग की जानकारी मिलने पर किसी दुकान से भी कोई प्रतिबंधित कीटनाशक दवाई नहीं मिली।

अक्टूबर 2023 में उत्पादन प्रतिबंधित तो 2026 में कैसे हुआ उत्पादन...?

मामले में जब कृषि विभाग की एसडीओ श्रीमती डामोर से माही की गूंज ने जानकारी ली तो बताया, प्रतिबंधित मोनोक्रोटोफॉस की 1 लीटर वाली बोतल खवासा में बस स्टैंड से एक किसान के पास से जप्त की। तथा जिस व्यापारी के यहां से किसान ने प्रतिबंधित कीटनाशक की बोतल लाना बताया उक्त व्यापारिक के दुकान व गोदाम पर छापा मार कार्रवाई की गई लेकिन वहां से कोई भी प्रतिबंधित कीटनाशक की बाटल नहीं मिली।

श्रीमती डामोर ने बताया कि, प्रतिबंधित कीटनाशक के उत्पादन व विक्रय की जब्ती का पंचनामा बनाया गया है, उक्त कार्रवाई की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को आज देंगे और वे जिस तरह की कार्रवाई के आदेश देंगे वह कार्रवाई करेंगे।

कृषि विभाग के कार्रवाई के 24 घंटे बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में प्रतिबंधित कीटनाशक कार्रवाई की जानकारी व वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं देना ही दर्शाता है कि, उक्त यह संवेदनशील मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि भारत सरकार के प्रतिबंध के बाद उक्त मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक दवाई करीब तीन वर्ष बाद उत्पादन किया व महाराष्ट्र से सप्लाई होकर मध्य प्रदेश के अंतिम छोर खवासा तक पहुंचा। लेकिन उक्त प्रतिबंधित कीटनाशक भारत सरकार के प्रतिबंधित के बाद किस तरह से उत्पादन हुई? और उक्त उत्पादन की यह कीटनाशक दवाई देश के किन-किन क्षेत्र व गांव तक पहुंची? की प्रमुखता से जांच कर पूरे प्रतिबंधित कीटनाशक माफियाओं के गिरोह तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन लगता है जिले का पंगु कृषि विभाग के नुमांइदे ले-देकर मामले को बिना एफआईआर व जांच के ही मामला रफा-दफा करने का प्रयास कर रहे! फिर भी आगे देखना है कि, कृषि विभाग की यह कार्रवाई कहां तक पहुंचती है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422